सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
YouTube
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 87, नई दिल्ली, मंगलवार, 24 जनवरी 2023, पेज 8

NEWS TRANSPORT VISHESH NTV
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये
परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 कर्तव्य पथ पर परेड देखने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो कराएगी फ्री यात्रा
05 क्या सच में गायब हो जाएंगी पेट्रोल कारें?
08 कोरोना के बाद अब भारत में नोरोवायरस दे रहा टेंशन

आज का सुविचार

जिस व्यक्ति का मन का भाव सच्चा होता है, उस व्यक्ति का हर काम अच्छा होता है।

गडकरी ने मध्य प्रदेश में 6,800 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया

- 28 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई 550 किमी है।

संजय बाटला

नयी दिल्ली, भाषा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के ओरछा में 6,800 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 28 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई 550 किमी है। गडकरी ने कहा कि पवई, ओरछा, हरपालपुर, कैथी पडरिया कला, पटना तमौली, जस्सो, नागौद और सागर लिंक रोड बाइपास के निर्माण से शहर में यातायात का दबाव कम होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे के निर्माण से सीमेंट और खनिजों का परिवहन आसान हो जाएगा और लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो जाएगी।

मंत्री ने कहा कि इस गलियारे के बनने से भोपाल से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी का संपर्क बेहतर होगा। टीकमगढ़ से ओरछा तक पक्की शोल्डर वाली 2 लेन सड़क के निर्माण से यातायात सुरक्षित होगा।

गडकरी ने 2,000 करोड़ रुपये की लागत से बमीठा से सतना तक 105 किलोमीटर लंबी चार लेन वाली नई सड़क के निर्माण की भी घोषणा की। इस सड़क के बनने से टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इनसाइड

30 साल बाद फिर कर सकेंगे डबल डेकर बसों में सफर

नई दिल्ली। करीब 30 साल बाद एक बार फिर दिल्लीवासियों को दोबारा डबल डेकर बसों में सफर का मौका मिलेगा। परिवहन विभाग ने 25 ऐसी डबल डेकर बसों का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान बस सेवा की शुरुआत की योजना है। कुछ दिन पहले उपराज्यपाल ने समीक्षा बैठक में डबल डेकर बसें चलाने के लिए संभावनाएं तलाशने का निर्देश के बाद तैयारियां तेज हो गई हैं। 1970 के दशक में दिल्ली की सड़कों पर डबल डेकर बसों की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में दो डेक में चालक की केबिन, यात्रियों से अलग होती थी। ट्रेलर बसों के नाम से मशहूर थीं। कुछ साल बाद बदलाव के बाद 1982 में 20 डबल डेकर बसें श्रीनिवासपुरी डिपो (ओखला-1) डिपो से अलग-अलग रूट पर चलाई गईं। इनमें मुद्रिका, लाल किला से प्रेस एन्क्लेव सहित दूसरे मार्गों पर डबल डेकर बसें 1990 के दशक की शुरुआत तक चलती रहीं। लेकिन बदलते समय में इसकी कम होती उपयोगिता और रिंग रोड पर बने पुल और फुटओवर ब्रिज की ऊंचाई के कारण इसे बंद कर दिया गया था। डीटीसी की मुद्रिका (डबल डेकर) बसें पहले लाजपत नगर से कश्मीरी गेट के बीच चलती थीं। लाल किला के पीछे सलीमगढ़ ब्रिज की कम ऊंचाई होने की वजह से बसें कश्मीरी गेट से दोबारा लाजपत नगर के लिए लौट जाती थीं। मुद्रिका बसें रिंग रोड पर एक ही तरफ की सड़क से घूमती हुई दोबारा वहीं लौटती है। लेकिन पुल होने की वजह से केवल सिंगल स्टोरी बसें ही इस रूट पर चल सकती हैं। माना जा रहा है कि जी-20 से पहले डबल डेकर बसों को केवल उन मार्गों पर चलाया जाएगा जिन रास्ते पर कम ऊंचाई के फुटओवर ब्रिज या पुल नहीं हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 25 डबल डेकर बसों का प्रस्ताव परिवहन मंत्री को भेजा है। इसके लिए संभावित रूट भी बताए गए हैं ताकि देश विदेश के मेहमानों को दिल्ली में भी विश्वस्तरीय परिवहन सुविधाएं मिल सके।

यूपी के 23 बस अड्डों का करोड़ों की लागत से होगा कायाकल्प, देश के 35 नामी निवेशक लगाएंगे पैसा

एनटीवी संवाददाता

पीपीपी माडल के तहत यूपी के 23 बस अड्डों को विकसित अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। यह सभी बसअड्डे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए बहुमंजिला बनाया जाएगा जहां यात्रियों को माल रेस्टोरेंट पार्किंग दफ्तर बैंक आदि सुविधाएं मिलेंगी।

गाजियाबाद। गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के कुल 23 बस अड्डों को 2607 करोड़ की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर बनाकर कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए 25 जनवरी को गाजियाबाद के कौशांबी स्थित रेडिशन ब्लू होटल में देश के 35 नामी निवेशकों के साथ बैठक होगी। उसमें निवेशकों को किस बस अड्डे पर कितनी लागत से क्या काम होना है इसका पूरा विवरण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 23 बस अड्डों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इन बस अड्डों को एक या बहुमंजिला बनाया जाएगा, जहां पर माल, रेस्टोरेंट, पार्किंग, दफ्तर, बैंक आदि सुविधाएं मिलेंगी। इससे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की आय भी बढ़ेगी। साथ ही लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी।

आठ मंजिला होगा कौशांबी डिपो

पूरे प्रदेश में आनंद विहार के सामने गाजियाबाद के कौशांबी डिपो को सबसे ज्यादा 261 करोड़ रुपये की लागत से सुविधाजनक बनाया जाएगा। यहां भूतल के नीचे दो मंजिला बेसमेंट में पार्किंग और बसों की वर्कशाप होगी। भूतल से बसें चलेंगी। उसके ऊपर पांच मंजिला इमारत में माल, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, दफ्तर आदि होंगे। इसी तरह प्रदेश के अन्य बस अड्डों पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं शुरू करने का काम किया जाएगा।

बैठक में 35 बड़े निवेशक ले रहे हिस्सा

यूपी के बस अड्डों को कायाकल्प करने के लिए देश के बड़े निवेशकों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें अदानी समूह, शालीमार समूह, उप्पल चड्ढा हाइटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि., प्रतीक समूह, सनसिटी हाइटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., चित्रा रीयलकान प्रा. लि., अपेक्स समूह, यूपी टाउनशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. समेत अन्य बड़े निवेशक आ रहे हैं। मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे की ओर से निवेशकों को आमंत्रित किया गया है।

निवेशकों को दी जाएगी काम की जानकारी

यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक एके ने बताया कि 25 जनवरी को कौशांबी के रेडिशन ब्लू होटल में निवेशकों के साथ बैठक की जाएगी। बैठक केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की अध्यक्षता में होगी। यूपीएसआरटीसी के मुख्य महाप्रबंधक संजय शुक्ला, मेरठ मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व अन्य लोग मौजूद रहेंगे।

किन बस अड्डे को कितनी जमीन और लागत से बनाया जाएगा

डिपो - स्क्वायर मीटर एरिया - लागत (करोड़ में)
कौशांबी - 24284- 261
साहिबाबाद - 15000- 161
गाजियाबाद - 10036 - 62
विभूति खंड गोमती नगर - 31497 - 243
चारबाग बस स्टेशन - 6784- 50
अमौसी लखनऊ - 20170 - 154
कानपुर सेंट्रल - 22073 - 143
वाराणसी कैंट - 13315 - 96
बुलंदशहर - 10300 - 64
गढ़मुक्तेश्वर - 25000 - 148
सिविल लाइन प्रयागराज - 18000 - 110
जीरो रोड डिपो प्रयागराज - 6265 - 39
सोहराब गेट मेरठ - 11580 - 80
ट्रांसपोर्ट नगर आगरा - 30744 - 193
ईदगाह आगरा - 8000 - 52
आगरा फोर्ट- 4046 - 25
रसूलाबाद अलीगढ़ - 18982 - 128
मथुरा ओल्ड - 6790 - 44
गोरखपुर - 14416 - 92
अयोध्या धाम - 36426 - 219
बरेली - 20164 - 137
मिर्जापुर - 9152 - 63
रायबरेली - 5982 - 43

कई लोग इलाज के लिए मुंबई जाते हैं, यह उपयोगी जानकारी है कृपया इसे जरूर पढ़ें

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। डी मार्ट डी मार्ट के प्रमोटर राधाकिशन दमानी ने मुंबई में इलाज करा रहे मरीजों के परिवारों के लिए 53 कमरों के साथ *ए मेट्रो सिनेमा क्वींस रोड मुंबई के पास गोपाल हवेली में एक सुविधा का निर्माण किया है। इसका उद्घाटन कल किया गया। यह बहुत अच्छे से किया। शुभचिंतकों की ऐसी किसी भी वास्तविक आवश्यकता का उल्लेख किया जा सकता है।

पता: गोपाल हवेली
50, क्वीन रोड (सिनेमा लेन)
मेट्रो सिनेमा के पा, मुंबई 400 020
संपर्क जानकारी:
व्हाट्सएप एप्लीकेशन। गतिमान
91 88799 86893
ईमेल: fd@gpalmansion.com
gm@gpalmansion.com
दूरभाष नं: 022 22055001/02
www.gpalmansion.com
दरें हैं बहुत ही उचित
नाश्ता 30
लंच प्लेट 75
खाने की थाली 75
800 कमरे
रसोई और भोजन कक्ष बहुत विशाल।
कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सब कैसे हैं
मुंबई में आपातकालीन रिश्तेदारों के मामले में, पी.एल. इस जानकारी को सभी के साथ साझा करें। * हम मरीजों और रिश्तेदारों को मुफ्त टिफिन प्रदान करते हैं। *क्षेत्र - दक्षिण मुंबई
अस्पताल:- जसलोक, सैफी, बॉम्बे, नायर, जेजे, मुंबई सेंट्रल और वीटी के पास ....
संपर्क जानकारी:-
आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं
कल्पेश लोढ़ा 9967236006
मनोज पटवारी 9820645070
अमृत जैन 9029373751
कम से कम ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ें जो आगे बढ़ सकें और दूसरों की मदद कर सकें।
* आर.के. होम मेडिकल डिवाइसेस को एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लॉन्च किया गया है।
* व्हीलचेयर
* सक्शन मशीन
* पानी का बिस्तर
* एयरबेड
* केर टैक्स
उपयोग करने के लिए निः शुल्क (वापसी योग्य जमा के साथ)
संपर्क व्यक्ति:-
संजय शाह 9322516628
चिंतन पंड्या :- 7666311942
*जोड़ें:-17-डी, निसारगा उत्तर प्रदेश। आईडीबीआई बैंक के पास, महावीर नगर, कांदिवली पश्चिम मुंबई 67 67 *
साईं वल्यात्री साक्षरता पॉलीक्लिनिक
₹कंबर दरबार₹ शांतिलाल मोदी रोड, भूराभाई हॉल के सामने, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई।
* टी: 02265811644 *
0222865 9615
www.kambardarbar.org
* दिन का समय *
1. सामान्य ओपीडी ₹1/- केवल दवाओं सहित
दैनिक 11-30 पूर्वाह्न और 4-30 अपराह्न
2. एक्स-रे ₹100/-
प्रतिदिन 9 से 5-00 . तक
3. ईसीजी ₹70.00
प्रतिदिन _ * * * सुबह 9 बजे से 11.00 बजे तक *
. *पैथोलॉजी अत्यधिक सब्सिडी वाली दरें। केवल सीबीसी ₹20/-।
दैनिक 8.30 से 12.00
. *आंखों की जांच 20/-
3.30.30 दैनिक
सुबह_ 9 बजे: बुध, शुक्र, शनि।
मोतियाबिंद सर्जरी: सर्वश्रेष्ठ भारतीय लेंस के साथ निःशुल्क।
लेजर (फेको) सर्जरी:
5,300/- यू.एस. फोल्डेबल लेंस आयात करना
/ 10,000/- यूके ने फोल्डेबल हरफेरिक लेंस का आयात किया। (बाहरी दर 40,000/- है
. *स्त्री रोग/आईवीएफ/हिस्टेरोस्कोपी _मंगल/गुरु/शुक्र। दोपहर 1 बजे
7. *त्वचा का फटना। * .00 20.00
सोमवार दोपहर ..pm
8. आर्थोपेडिक 20.00
मंगलवार 3.30.30_
9. मधुमेह और कार्डियो .00 20.00
बुधवार रात 8:30 बजे।
10. *बच्चे का विभाजन। * .00 20.00
शुक्रवार शाम 5.30 बजे
11. कान/नाक/गला *.00 20.00
बुधवार / शुक्रवार शाम 4-30 बजे_
12. दंत चिकित्सा नाममात्र शुल्क आरसी शुल्क: ₹750/-।
प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सायं 0.00 बजे से सायं 00.00 बजे तक
1.. डायलिसिस बीपीएल मरीजों के लिए निःशुल्क
दैनिक (फोन: 28067645)
14. सर्वाइकल कैंसर (सर्वाइकल कैंसर) टेस्ट फ्री
15. एंटी कैंसर इंजेक्शन 14 से 24 साल की उम्र की लड़कियों के लिए।
16. वरिष्ठ नागरिकों के लिए वास्तविक सुनवाई, वास्तविक लागत का 50%। जन्म के समय पात्र बच्चों के लिए निःशुल्क।
1.. *गर्मी की छुट्टियों के दौरान सभी छात्रों को रियायती दरों पर नोटबुक और अन्य हार्डवेयर आइटम।
18. * बी.बी. एमबीबीएस सीए सीएस बी.पी.एच.आर.एम. एम.सी.ए. और एमबीए चुना। छात्रों के लिए पात्र उम्मीदवारों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति *। *उपहार
www.kamberda bar.org और सभी आवश्यक संपार्श्विक के साथ फॉर्म जमा करें।
कृपया संपर्क करें p_zijn zasainani@rediffmail.com ईमेल
किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

"निगम प्रबंधन अब भी नहीं जागा तो 31 जनवरी की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी"

रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल से 50 बसों के चक्के जाम

एनटीवी संवाददाता

टनकपुर/ लोहाघाट (चंपावत)। उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन की कार्यशैली के विरोध में रोडवेज के कर्मचारी सोमवार को सड़क पर उतर आए। पूर्व घोषित आंदोलन के तहत उन्होंने एक दिनी हड़ताल कर क्षेत्रीय कार्यशाला गेट पर धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मियों की हड़ताल की वजह से टनकपुर डिपो की 40 और लोहाघाट डिपो की 10 बसों के चक्के जाम रहे। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सोमवार को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट टनकपुर, लोहाघाट और पिथौरागढ़ के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन किया। यहां क्षेत्रीय कार्यशाला गेट पर हुए प्रदर्शन में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज कर निगम को निजी हाथों में सौंपने का षडयंत्र रचा जा रहा है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनुबंधित बसों का संचालन बढ़ाना, मानक से अधिक अनुबंधित बसों को निगम के बस बेड़े में शामिल करना, निगम के ढांचे के अंतर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपनल और पीआरडी से कर्मचारियों की तैनाती, पूर्व से तैनात कर्मचारियों को नियमित न करना निगम प्रबंधन की षडयंत्र का ही हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि प्रबंधन की इस मंशा का कर्मचारी एकजुटता के साथ कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन अब भी नहीं जागा तो 31 जनवरी की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। लोहाघाट में 15 में दस बसों का संचालन न होने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इस वजह से टैक्सियों में खासी भीड़ रही। यात्री मुन्नी देवी, केशवी देवी, फकीर राम, हरीश सिंह, दिनेश भट्ट, हरीश जोशी आदि का कहना है कि रोडवेज कर्मियों की हड़ताल से निपटने के लिए प्रशासन को वैकल्पिक उपाय करने चाहिए थे।

टनकपुर में धरना-प्रदर्शन में मोर्चा के संयोजक राजेंद्र सिंह मलिक, हुकुम चंद, नीरज सिंह के अलावा कैलाश मुरारी, वीरेंद्र पुरी, इंद्र सिंह बिष्ट, विमला बिष्ट, धर्मेंद्र सिंह, जगदीश जोशी, भुवन भट्ट, राजेंद्र सिंह, विनोद नौटियाल, संजीव कुमार, सूरजभान, कैलाश भट्ट, मनोज मिश्रा, आशा चंद, जमुना देवी, संजय भट्ट, रेवाधर चौड़ाकोटी, शेर सिंह बिष्ट, परवीन जोशी, कश्मीर सिंह, रमेश मुरारी, खीम राम, अमरेंद्र सिंह, शलज सक्सेना आदि मौजूद रहे।

रोडवेज को हुआ लाखों का नुकसान

टनकपुर। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल से टनकपुर, लोहाघाट और पिथौरागढ़ डिपो से बसों का संचालन ठप रहा। बसें नहीं चलने से जहां यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं रोडवेज को भी लाखों रुपये राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तराखंड के अन्य डिपो और यूपी की बसों का संचालन सुचारु रहने से यात्रियों को थोड़ी राहत मिली। टनकपुर डिपो के सहायक मंडलीय प्रबंधक (संचालन) केएस राणा के मुताबिक हड़ताल के कारण टनकपुर से 40 बसें नहीं चलीं। इससे डिपो को करीब 9 लाख रुपये राजस्व का नुकसान हुआ है।

लोहाघाट डिपो से इन मार्गों पर प्रभावित रही बस सेवा:

दिल्ली और देहरादून के लिए तीन-तीन, बरेली, हल्द्वानी, नैनीताल और काशीपुर के लिए एक-एक बस सेवा।

रोडवेज की बसों का संचालन प्रभावित होने से छह मार्गों पर दस बस सेवा प्रभावित हुई। करीब चार लाख रुपये राजस्व का नुकसान हुआ।

-नरेंद्र कुमार गौतम, एजीएम, रोडवेज, लोहाघाट।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

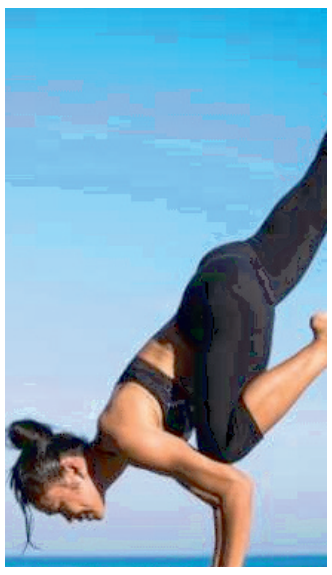

महिलाएं हर दिन करें ये 3 योगासन, बिना जिम के मिलेगा स्लिम-ट्रिम लुक

एक्सरसाइज या योग करना सेहत के लिए फायदेमंद है. नियमित योग और एक्सरसाइज करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. इससे कई बीमारियों से निजात भी मिलती है. बिजी रहने की वजह से या घर से बाहर न जाने की आदत के चलते कई बार महिलाओं के लिए जिम या योग केंद्र जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. कई बार महिलाएं चाहते हुए भी जिम नहीं जा पाती हैं और अपनी सेहत के साथ समझौता कर लेती हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो घर में रहकर भी कुछ खास योगासन की मदद ले सकती हैं. जो आपको स्वस्थ रखने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं.

यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट की क्लीनिकल योग इंस्ट्रक्टर डॉ. वंदना अवस्थी से उन योगासनों के बारे में जानते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने के साथ कई बीमारियों से राहत देने में मदद करेंगे. वैसे तो कोई भी आसन सुबह के समय करना बेहतर होता है लेकिन समय न मिलने पर जब भी करें तो खाना खाने के बाद कम से कम दो घंटे का गैप जरूर रखें. इतना ही नहीं इन योगासनों को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

चक्की चलनासन

इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट बिछाकर बैठ जायें. अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर मैक्सिमम गैप बनाएं. इस दौरान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे. अब हाथों को जमीन पर एकदम सामने की ओर सीधा रखकर उंगलियों को आपस में फंसा लें. फिर अपने हाथों को क्लॉक वाइज यानी दायीं से बायीं तरह गोल-गोल उसी तरह से घुमायें जैसे चक्की चलाई जाती है. इसके बाद विपरीत दिशा में यही प्रक्रिया दोहराएं. इस योगासन को शुरू में एक-दो मिनट करें फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ाएं. इस योगासन से पीसीओडी की दिक्कत में राहत मिलती है. जिससे अनियमित मासिक धर्म धीरे-धीरे नियमित होने लगता है साथ ही दर्द और ऐंठन से भी राहत मिलती है. इतना ही नहीं ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने और मोटापे से निजात दिलाने में भी मदद करता है.

तितली आसन

तितली आसन करने के लिए योगा मैट पर सूर्य की ओर मुख कर के आराम की मुद्रा में बैठें. फिर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर इस तरह से मोड़ें जिससे दोनों पैरों के तलवे आपस में मिल जायें. अब दोनों हाथों से पैर के तलवों को अच्छी तरह से पकड़ लें.अब तितली की तरह अपने पैरों को हिलाएं. इस आसन को भी शुरू में एक-दो मिनट करें फिर अपनी कैपिसिटी के अनुसार धीरे-धीरे इसका समय बढ़ाएं. तितली आसन करने से भी पीसीओडी की दिक्कत से राहत मिलती है. साथ ही पीठ का दर्द और मसल्स स्ट्रेस भी दूर होता है. इतना ही नहीं इस आसन को तीन महीने की गर्भावस्था के बाद भी किया जा सकता है. ये आसन डिलीवरी को आसान बनाने में भी मदद करता है. नियमित रूप से तितली आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

दंडासन

दंडासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जायें और पैरों को सामने की ओर फैला कर आपस में मिला लें. फिर दोनों हाथों को कंधों के बराबर अपनी जांघों के पास सीधा जमीन पर रखें.इस बीच रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें. अब दोनों पैरों के पंजो को अपनी ओर खींचें, कुछ सेकेंड रोक कर रखें फिर ढीला छोड़ दें. इस प्रक्रिया को दस से पंद्रह बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहराएं.

इन चीजों को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं महिलाएं, हमेशा रहेंगी हेल्दी एंड हैप्पी

वर्चुअल एक्सरसाइज क्लासेस के जरिये भी आप फिट रह सकती हैं.

हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कुछ अमेजिंग फिटनेस टिप्स, जिसे फॉलो करके आप नए साल की फ्रेश और एक्टिव शुरूआत कर सकती हैं.

ऑनलाइन एक्सरसाइज

कोरोना का डर एक बार सबको फिर से सताने लगा है. ऐसे में खुद को फिट एंड फाइन रखना बहुत जरूरी है. इसलिए भीड़ में जाये बिना आप वर्चुअल एक्सरसाइज क्लासेस लेने का सिलसिला शुरू कर सकती हैं. एक्सरसाइज का ये ट्रेंड फॉलो करके आप जिम गए बिना भी फिट रह सकती हैं.

फंक्शनल फिटनेस ट्राई करें

रोज सुबह फंक्शनल फिटनेस एक्सरसाइज ट्राई करके आप दिन की एनर्जेटिक शुरूआत कर सकती हैं. इन एक्सरसाइज को करने के लिए आप घर पर रहते हुए योगा या फिटनेस एक्सपर्ट के ऑनलाइन वीडिओ देख सकती हैं और बिना कुछ खर्च किये फिटनेस ट्रेनिंग ले सकती हैं.

घर पर जिम करें

आजकल के बिजी शेड्यूल में ज्यादातर लोगों को जिम जाने का समय नहीं मिल पाता है. जिसके चलते लोग फिटनेस को अवॉयड कर देते हैं. ऐसे में नए साल पर घर में जिम सेटअप करके आप अपनी हेल्थ को बेस्ट गिफ्ट दे सकती हैं. इससे आप कम टाइम में डेली वर्कआउट कर सकेंगी.

फिटनेस एक्टिविटी करें

अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद करती हैं. तो ऐसे में नए साल पर आप मॉर्निंग वॉक, आउटडोर एक्सरसाइज, साइकलिंग और गेम्स खेलने जैसी फिजिकल एक्टिविटीज करके फिट रहने के साथ-साथ दिन की भी बेस्ट शुरूआत कर सकती हैं.

डांस प्रैक्टिस करें

अगर आप डांस करने की शौकीन हैं, तो नए साल में डांस को अपने डेली रूटीन में शामिल करके फिट रह सकती हैं. बता दें कि डांस का ये फिटनेस ट्रेंड आपका हेल्थ सीक्रेट बन सकता है. ऐसे में भांगड़ा, जुम्बा, हिप हॉप और क्लासिकल डांस करके आप फिटनेस के साथ अपनी हॉबी भी निखार सकती हैं।

सर्दियों में इन चीजों को खाने से बचें महिलाएं

सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादातर महिलाएं हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो करती हैं. डाइटिशियन भी सर्दियों में घी, ड्राई फ्रूट्स, गुड़, अदरक, शकरकंद, गाजर, सरसों का साग और केसर जैसी चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. सर्दियों के दौरान ज्यादातर महिलाएं आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी ठंडी चीजें भी खाना पसंद करती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्दियों में ठंडी चीजें खाने से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं. आइए आपको बताते हैं सर्दी में ठंडी चीजों का सेवन करने के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में.

पेट की प्रॉब्लम्स

हेल्थशॉट्स के अनुसार सर्दियों में ठंडा खाना खाने से आपको पेट से जुड़ी कई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं. मसलन सर्दियों में ठंडी चीजों का सेवन करने से आपको पेट में सूजन, ऐंठन, पेट फूलना, थकान, बॉडी में शॉक महसूस होना और पाचन तंत्र वीक होने जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

शरीर का तापमान कम होना

सर्दी के मौसम में बाहर का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है. ऐसे में ठंडी चीजें खाने से आपकी बॉडी का टेंप्रेचर भी कम होने लगता है. जिससे ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा असर पड़ता है और आपका खून जम भी सकता है.

गले में हो सकता है इंफेक्शन

जानकारों के अनुसार सर्दियों में ठंडा खाना खाने से आपको गले में थ्रोट इंफेक्शन हो सकता है. खासकर सर्दी के मौसम में कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे जूस पीने से आपको गले में खुजली, जलन और इरिटेशन होने लगती है. ऐसे में गले का खास ख्याल रखने के लिए आप गर्म दूध, सूप, नट्स, मसाले और हर्ब्स का सेवन कर सकते हैं.

जुकाम होने का खतरा

सर्दी के मौसम में बॉडी काफी सेंसटिव हो जाती है. ऐसे में ठंडी चीजों का सेवन करना बीमारी को बुलावा देने जैसा होता है. बता दें कि सर्दियों के दौरान ठंडी चीजें खाने से आप खांसी, जुकाम, बुखार और सीजनल फ्लू जैसी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं.

पाचन पर पड़ेगा बुरा असर

सर्दियों में ठंडी चीजों का सेवन पाचन तंत्र को भी खासा प्रभावित करता है. दरअसल ठंडी चीजें काफी हैवी होती है. जिसे पचाने में आपको काफी दिक्कत आ सकती है. वहीं पाचन तंत्र कमजोर होने से आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है.

कुछ सामान्य लक्षण जो 5 तरह के गाइनेकोलॉजिकल कैंसर में होते हैं कॉमन, आप भी दें ध्यान

कैंसर एक जानलेवा बीमारी है. यदि इसका समय रहते इलाज शुरू ना किया जाए तो कई गंभीर मामलों में व्यक्ति की जान चली जाती है. बॉडी में ट्यूमर सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सिर्फ एक बॉडी पार्ट के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए खतरे की घंटी बन सकती है. कैंसर के कुछ ऐसे प्रकार हैं, जो सिर्फ महिलाओं को इनफेक्ट कर सकते हैं. ऐसे में महिलाओं में कैंसर की समस्या ज्यादा खतरनाक हो सकती है. ओवरीज, कोख या वेजाइना जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर असर करने वाले ये गाइनेकोलॉजिकल कैंसर ढेरों बड़ी परेशानियों का कारण बन सकते हैं. सही समाधान के लिए सही समय पर बीमारी की पहचान कर, सही इलाज कराना जरूरी है. दवाइयों के साथ सही ट्रीटमेंट की मदद से इन परेशानियों से निजात पाई जा सकती है. आइए जानते हैं 5 तरह के गाइनेकोलॉजिकल कैंसर में कौन से आम लक्षण देखे जाते हैं :

एमडैंडरसन डॉट ओआरजी के अनुसार, वुलवर कैंसर के अलावा सभी गाइनेकोलॉजिकल कैंसर में ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिलती है. वेजाइना से किसी भी तरह के डिस्चार्ज या ब्लीडिंग को नजरंदाज करना घातक साबित हो सकता है. पेट दर्द के साथ ही कमर दर्द भी किसी बड़े खतरे की दस्तक हो सकती है. ऐसे में सही समय डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लें.

-बार-बार पेशाब आना किसी गंभीर स्थिति की ओर इशारा हो सकता है. लगातार टॉयलेट जाने की शिकायत कैंसर के साथ ही अन्य परेशानियों का भी लक्षण हो सकती है. ऐसे में जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह करा लें.

-वेजाइना या दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में खुजली, जलन और ज्यादा सेंसटिविटी कैंसर का लक्षण हो सकती है. इन्फेक्शन में भी ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं, ऐसे में इन्हें इग्नोर करने का रिस्क लेने से बचें.

-सेक्स के दौरान या बाद में ज्यादा असामान्य दर्द महसूस होने पर जरूरी टेस्ट अवश्य करा लें. ये दर्द गाइनेकोलॉजिकल कैंसर के शुरुवाती लक्षणों में शुमार है.

-पेडू या पेल्विक एरिया में दर्द होना कैंसर की ओर संकेत करता है. बार-बार इस तरह का दर्द होने पर डॉक्टर को अवश्य दिखा लें नहीं तो समस्या के गंभीर होने की संभावना बढ़ जाती है.

-खाना खाने में असहजता, पेट जल्दी भर जाना, भूख कम लगना या सूजन भी गाइनेकोलॉजिकल कैंसर का संकेत हो सकता है. ऐसे में घबराने की जगह सही उपचार का ख्याल करें.

क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए प्रोटीन ? जानें डाइट में शामिल करने से क्या-क्या होते हैं फायदे

प्रोटीन के सेवन से आपको देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं. ऐसे में यह उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है

प्रोटीन के सेवन से देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं.प्रोटीन के सेवन से देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं.

प्रोटीन पुरुषों के साथ ही महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी होता है. इससे हेल्दी और फिट बॉडी लंबी उम्र तक बनाए रखने में मदद मिलती है. साथ ही, प्रोटीन मांसपेशियों के विकास और मसल्स फाइबर की मरम्मत के लिए भी जरूरी होता है. प्रोटीन एक प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जो मसल मास और फिजिक को बनाए रखता है. महिलाओं के लिए प्रोटीन का सेवन बहुत महत्वपूर्ण होता है. प्रोटीन की जरूरत उम्र, एक्सरसाइज लेवल, कैलोरी इनटेक और अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है. चूंकि, शरीर सभी आवश्यक अमीनो एसिड का निर्माण नहीं करता है, इसलिए सप्लीमेंट या डाइट में प्रोटीन को जरूर शामिल करना चाहिए. प्रोटीन, वसा और कार्ब्स के विपरीत, स्टोर नहीं किया जा सकता है. ऐसे में हर दिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है.

महिलाओं के लिए प्रोटीन के फायदे

हेल्थकार्ट डॉट कॉम में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रोटीन बालों, त्वचा और नाखूनों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी होता है. ये सभी केराटिन से बने होते हैं, जो एक तरह का संरचनात्मक प्रोटीन है. चूंकि, केराटिन प्रोटीन से बना होता है, इसलिए शरीर में इसका निर्माण जारी रखने के लिए प्रोटीन युक्त फूड्स का सेवन करना जरूरी है. कोलेजन भी एक प्रोटीन है, जो हमारी त्वचा के वजन का 70% हिस्सा होता है. यह शरीर का सबसे प्रमुख प्रोटीन है, जो कनेक्टिव टिशूज में पाया जाता है. यह जोड़ों को स्थिर और गतिशील बनाए रखने में मदद करता है. प्रोटीन की कमी होने से समय से पहले त्वचा पर झुर्रियां पड़ सकती हैं.

मांसपेशियों को रखे मजबूत

महिलाओं के लिए प्रोटीन मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है, क्योंकि यह अमीनो एसिड में उच्च होता है और मांसपेशियों में ऐंठन को दूर करता है. इससे लीन मसल मास बनाए रखने में मदद मिलती है. महिलाओं को उम्र बढ़ने के साथ ऑस्टियोपोरोसिस, अन्य हड्डियों की समस्या होने का रिस्क अधिक रहता है, ऐसे में उन्हें डायटरी प्रोटीन का सेवन अधिक करना चाहिए, ताकि मसल मास में इजाफा हो.

वजन होता है कम

प्रोटीन के सेवन से आपको देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं. ऐसे में यह उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जो वजन कम करना चाहती हैं. जिनका वजन बहुत अधिक है, वे यदि प्रोटीन ड्रिंक्स लेती हैं, तो इससे बॉडी वेट, फैट मास और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में सुधार होता है.

हड्डियां रहती हैं स्वस्थ

महिलाओं को हड्डियों से संबंधित समस्याएं बहुत होती हैं, ऐसे में सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी लेने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के लिए प्रोटीन की भी जरूरत होती है. जब आप कम मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन करती हैं, तो प्रोटीन ही हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. अध्ययनों के अनुसार, उच्च प्रोटीन आहार लेने से बोन मिनरल डेंसिटी का लेवल अधिक और हड्डियों के नुकसान की दर कम होती है.

इनसाइड

सरकारी स्कूलों में क्लास 9वीं से 11 वीं तक के 15 फरवरी से शुरू होंगे फाइनल एग्जाम, चेक करें शेड्यूल

दिल्ली में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, एनडीएमसी स्कूलों में फाइनल एग्जाम 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट के फाइनल एग्जाम शुरू होने की तारीख, परीक्षा शेड्यूल और गाइडलाइंस शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिए हैं। फाइनल एग्जाम 15 फरवरी से 18 मार्च तक चलेंगे।

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों समेत एनडीएमसी स्कूलों में क्लास 9 और 11 के लिए सालाना परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। शिक्षा निदेशालय ने इन परीक्षाओं के लिए शेड्यूल और दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। क्लास 9 और क्लास 11 के एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे और 18 मार्च तक चलेंगे। क्लास 3 से लेकर 8 के एग्जाम 2:30 बजे से 5 बजे तक और क्लास 9 और 11 के एग्जाम 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होंगे। क्लास 3 के एग्जाम 9 मार्च, वहीं क्लास 4 से लेकर क्लास 8 के एग्जाम 2 मार्च से शुरू होंगे। सभी क्लासेज के एग्जाम 18 मार्च को खत्म होंगे। क्लास 9 के एग्जाम की शुरुआत नैचुरल साइंस के पेपर और 11वीं के फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस के पेपर के साथ होगी। जो पेपर शेड्यूल में नहीं हैं, उनकी परीक्षाएं स्कूल स्तर पर कराई जाएंगी। क्लास 3 से 5 के कॉमन क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर्म में होंगे। मॉर्निंग स्कूलों में क्लास 3 से 8 के लिए टीचिंग वर्क 15 फरवरी से 28 फरवरी तक और ईवनिंग स्कूलों में 16 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रहेगा। यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में असिस्टेंट प्रफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होने वाला UGC नेट एग्जाम के लिए सोमवार को शाम 5 बजे तक आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के मुताबिक, कैंडिडेट्स की ओर से यह मांग की जा रही थी कि आवेदन करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। कुछ कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ अपनी फोटो और जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए थे और कुछ को फीस जमा करने में दिक्कत हो रही थी। इसको देखते हुए NTA ने तय किया है कि 23 जनवरी को शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है और रात 11.50 तक ऐप्लीकेशन फीस जमा हो सकती है। साल 2023 में UGC नेट एग्जाम का पहला सत्र 21 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। इसका दूसरा सत्र जून में आयोजित होगा।

5 स्टार होटल को 23 लाख का चूना लगाने वाला शख्स अरेस्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस में करीब साढ़े तीन महीने स्टे करने के बाद होटल के 23 लाख रुपये से अधिक का बिल चुकाए बिना होटल से फरार होने वाले आरोपी मेहमेद शरीफ को पकड़ लिया गया है। उसे लोकल सरोजिनी नगर थाना पुलिस ने नहीं बल्कि जिले के स्पेशल स्टाफ और डीआईयू ने पकड़ा है। वह दिल्ली से भागकर कर्नाटक राज्य में स्थित अपने घर छिप गया था। उसे कर्नाटक के साउथ कन्नड़ जिले के मैंगलोर से पकड़ा गया।

कर्तव्य पथ पर परेड देखने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो कराएगी फ्री यात्रा, रखी ये शर्त

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC डीएमआरसी) ने दिल्ली मेट्रो में फ्री यात्रा उन लोगों के लिए सुविधा प्रदान की है जो गणतंत्र दिवस समारोह (Republic Day Parade) में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ई-निमंत्रण कार्ड या ई-टिकट दिखाना होगा।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC, डीएमआरसी) ने दिल्ली मेट्रो में फ्री यात्रा उन लोगों के लिए सुविधा प्रदान की है, जो गणतंत्र दिवस समारोह (Republic Day Parade) में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ई-निमंत्रण कार्ड या ई-टिकट दिखाना होगा। तभी उन्हें मुफ्त में दिल्ली मेट्रो की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

स्पाइसजेट की दिल्ली-हैदराबाद फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी, दो यात्रियों को उतारा गया

दिल्ली से हैदराबाद जा रहे एक स्पाइसजेट के एक विमान में केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार की घटना के आरोप में एक यात्री को विमान से नीचे उतार दिया गया।

नई दिल्ली। दिल्ली से हैदराबाद जा रहे स्पाइसजेट के विमान में एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी करने की घटना सामने आई है। एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी करने वाले यात्री और उसके सहयात्री को विमान से नीचे उतार दिया गया।

दिल्ली से हैदराबाद जा रही थी फ्लाइट

केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आने के बाद एक यात्री को विमान से नीचे उतार दिया गया है। स्पाइसजेट की ओर से एक बयान में कहा कि गया कि 23 जनवरी, 2023 को स्पाइसजेट के वेट-लीज्ड कोरेंडन विमान को दिल्ली से हैदराबाद के निर्धारित किया गया था। दिल्ली में बोर्डिंग के दौरान, एक यात्री ने अनियंत्रित और अनुचित तरीके से व्यवहार किया, केबिन क्रू को परेशान किया और परेशान किया। केबिन क्रू ने पीआईसी और सुरक्षा कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी।

दो यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया

क्रू के साथ दुर्व्यवहार करने वाले यात्री और उसके एक सह-यात्री को विमान से नीचे उतार दिया गया। इसके बाद सुरक्षा दल को सौंप दिया गया। बता दें कि इससे पहले भी विमान में यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है।

इससे पहले भी ऐसी हुई हैं घटनाएं

खास बात है कि इसी साल 9 जनवरी को दिल्ली से दिल्ली से पटना आ रहे विमान में एयर होस्टेस और क्रू मेंबर के साथ नशेड़ी युवकों की बदसलूकी का मामला सामने आया था। इसके बाद नशे में धुत होकर हंगामा करने वाले दो युवकों को पटना एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था।

यहीं नहीं पिछले साल 29 दिसंबर को बैंकॉक से कोलकाता आ रही थाई एयरवेज की एक फ्लाइट में सीट को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों में कहासुनी यहां तक पहुंच जाती है, आपस में लोग हाथापाई पर उतर जाते हैं।

इसके अलावा दिसंबर 2022 में ही इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट में एयर होस्टेस और पैसेंजर दोनों को एक-दूसरे पर चिल्लाने का वीडियो सामने आया था।यात्री ने जहाज पर अपना खराब व्यवहार दिखाया और एक एयर होस्टेस का अपमान किया, जिसके बाद चालक दल के नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा।

26 जनवरी को अब रेस्तरां और बार में भी नहीं परोसी जाएगी शराब, देखें ड्राई डे की लिस्ट

अब 26 जनवरी पर बार और रेस्तरां में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। पहले 26 जनवरी को ड्राई डे घोषित होता था लेकिन बार और रेस्तरां में शराब परोसने की इजाजत थी। इस बार बार और रेस्तरां में भी शराब बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली में अब 26 जनवरी पर बार और रेस्तरां में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। पहले 26 जनवरी को ड्राई डे घोषित होता था लेकिन बार और रेस्तरां में शराब परोसने की इजाजत थी। इस बार पहली बार 26 जनवरी को बार और रेस्तरां में भी शराब बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को इसार आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही महाशिवरात्रि, रामनवमी और होली पर भी दुकानों पर शराब बिक्री पर पाबंदी रहेगी। सरकार ने स्वामी दयानंद जयंती और गुरु रविदास जयंती पर भी ड्राइ डे घोषित किया है, इस दिन भी शराब दुकान बंद रहेंगी।

कई दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

सरकार के आबकारी विभाग की ओर से एक जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ड्राइ डे की सूची जारी की है। इसमें सरकार ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, पांच फरवरी को गुरु रविदास जयंती, 15 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि, आठ मार्च को होली और 30 मार्च को राम नवमी पर ड्राइ डे घोषित किया है।

हर तीन महीने प जारी होती है ड्राइ डे की लिस्ट

इस दौरान शराब के ठेके बंद रहेंगे। दिल्ली में सरकार हर तीन महीने पर ड्राइ डे की सूची जारी करती है। वर्तमान में करीब 21 ड्राइ डे पूरे साल में पड़ते हैं।

पैरा-ग्लाइडर, ड्रोन और हॉट एयर बलून सहित कई गतिविधियों पर रोक, पुलिस ने तेज की पैट्रोलिंग

गणतंत्र दिवस 2023 (Republic Day 2023) को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राजधानी में कई ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी है जो सुरक्षा को देखते हुए नुकसानदायक हो सकती है।

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस 2023 (Republic Day 2023) को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राजधानी में कई ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी है, जो सुरक्षा को देखते हुए नुकसानदायक हो सकती है। पुलिस ने दिल्ली में पैरा-ग्लाइडिंग, ड्रोन सहित कई ऐसी चीजों पर रोक लगा दी है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोमवार से 15 फरवरी तक पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रो-लाइट विमान, दूर से संचालित विमान, हॉट एयर बलून, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकोप्टर की उड़ान पर रोक लगा दी है।

दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि 26 जनवरी को लेकर चेकिंग और पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने होटल्स, गेस्ट हाउस और सिनेमा हॉल में जाकर जांच पड़ताल की। यहां रह रहे लोगों से पूछताछ की। बड़े बाजारों में भी सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए बॉडी कैमरा का भी इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी है। परेड रूट के 3 किमी तक हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं।

दिल्ली के छावला में झगड़ा शांत करा रहे हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला, ICU में भर्ती

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले दिनों चाकू से हमले की वारदात में दिल्ली पुलिस के ASI शंभू दयाल की मौत हो गई थी। अब पुलिसकर्मी पर हमले का एक और मामला सामने आया है। छावला इलाके में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए हैं।

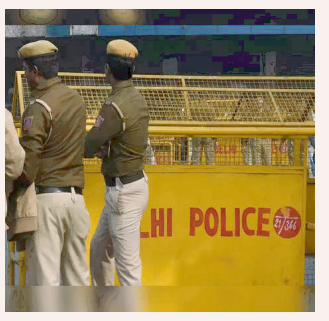

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के छावला इलाके में एक ऑटो रिक्शा चालक और कुछ लोगों के बीच हुए झगड़े को शांत कराते समय एक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार शाम की है, जब छावला थाने के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) सुनील और हेड कांस्टेबल रिंकू कुतुब विहार इलाके में गश्त पर थे। रात करीब आठ बजकर 35 मिनट पर उन्हें इलाके में एक झड़प होने की सूचना मिली थी। पुलिस उपायुक्त (द्वारका) हर्षवर्धन ने बताया कि जब दोनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तब कुछ लोग वहां एक ऑटो रिक्शा चालक से झगड़ा कर रहे थे। पुलिस ने जब झगड़ा रोकने की कोशिश की तब ऑटो रिक्शा चालक ने रिंकू पर चाकू से दो बार वार किया और वहां से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि ऑटो चालक की पहचान इलाके के अपराधी सनी ऊर्फ शूटर के रूप में हुई है।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने बताया कि रिंकू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल जाकर उनसे भेंट की है और उनके लिए हर संभव मेडिकल सहायता सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि छावला थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोकसेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना), 353 (सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने के लिए बल प्रयोग, उसके साथ मारपीट), 307 (हत्या का प्रयास), और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

घटना के बाद पुलिस ने सन्नी तथा उसके अन्य साथियों की तलाश शुरू की और उन्हें सूचना मिली कि वह कुतुब विहार में भाई-भाई रोड पर स्थित एक मकान में हैं। पुलिस देर रात करीब ढाई बजे जब मौके पर पहुंची,तब सन्नी ने उन पर गोलियां चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तीन गोलियां चलाईं, सन्नी के पैर में गोली लगी है। हर्षवर्धन ने बताया कि सन्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि कुल तीन लोगों को मकान से गिरफ्तार किया गया। मौके से एक देशी पिस्तौल, तीन कारतूस और एक चाकू भी बरामद किया गया है। घटना में संलिप्त अन्य लोगों की तलाश जारी है।

दिल्ली में माता-पिता को खो चुके छात्रों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा, शिक्षा निदेशालय ने मदद का बढ़ाया हाथ

एनटीवी संवाददाता

कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा निदेशालय आगे आया है। इन अनाथ बच्चों को अब फ्री में शिक्षा दी जाएगी। इन अनाथ छात्रों की फीस को माफ कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के दौरान राजधानी के निजी स्कूलों में पढ़ रहे बहुत से छात्रों ने अपने अभिभावकों को खोया है। जिसके बाद ये छात्र अनाथ हो गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने अब इन छात्रों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है।

अनाथ छात्रों की माफ होगी फीस

निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने कहा कि डीडीए और निजी जमीनों पर बने सभी निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र, जो कोरोना या अन्य कारणों से अनाथ हो गए हैं उन सभी की फीस माफ होगी। वहीं, सभी उप शिक्षा निदेशकों को छात्रों की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी।

निदेशालय ने कहा कि सरकार द्वारा आवंटित भूमि और निजी भूमि में संचालित होने वाले सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल और गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाले नर्सरी से आठवीं तक के वो छात्र जो वर्ष 2020 के बाद अनाथ हो गए हैं।

वंचित समूह में शामिल करने का निर्देश

उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या वंचित समूह (डीजी) के अंतर्गत शामिल किया जाए। स्कूल इस श्रेणी के सभी छात्रों की प्रतिपूर्ति का दावा शिक्षा निदेशालय से लेंगे। वहीं, नौवीं से 12वीं तक के जो छात्र वर्ष 2020 के बाद अनाथ हो गए हैं उन्हें तत्काल स्कूल फ्रीशिप श्रेणी में शामिल किया जाए और इस श्रेणी में लागू सभी लाभ छात्र को दिए जाए।

वहीं, निजी भूमि पर संचालित सभी निजी और अल्पसंख्यक स्कूलों में नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं के छात्रों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेकर पढ़ाई पूरी करने को लेकर मार्गदर्शित किया जाए। निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा कि किसी भी छात्र की आर्थिक कारणों से पढ़ाई बीच में ही न रुके इसके लिए निजी स्कूलों में पढ़ने वाले नौवीं से 12वीं तक के छात्र सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं।

रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट से बढ़ा निवेशकों में विश्वास, तेज हुई निवेश की रफ्तार

एनटीवी न्यूज

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कारिडोर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ मार्च 2019 को रखी थी। 82 किलोमीटर लंबे इस कारिडोर का कार्य तीन खंड में किया जा रहा है। प्राथमिक खंड साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबा है।

गाजियाबाद। जिले में निवेश को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट को जिला प्रशासन ने माडल बनाया है। जिसका कार्य तय समय पर ही पूरा होने की ओर अग्रसरित है, प्रोजेक्ट में आई दुविधाओं को जिला प्रशासन ने समय पर खत्म कराया, जिसकी वजह से वर्तमान में रैपिड ट्रेन का साहिबाबाद से दुहाई के बीच ट्रायल रन शुरू हो चुका है।

निवेश को दिया जाएगा और बढ़ावा

जल्द ही यात्रियों को सफर करने को मिलेगा। यही वजह है कि 25 जनवरी को कौशांबी में आयोजित गाजियाबाद इंवेस्टर्स समिट की बैठक में एनसीआरटीसी के अधिकारियों को भी गाजियाबाद में कार्य के दौरान हुए अपने अनुभव को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। जिससे कि जिले में निवेश को और बढ़ावा दिया जा सके।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कारिडोर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ मार्च 2019 को रखी थी। 82 किलोमीटर लंबे इस कारिडोर का कार्य तीन खंड में किया जा रहा है। प्राथमिक खंड साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबा है, जिस पर मार्च 2023 से यात्रियों के लिए रैपिड ट्रेन का परिचालन शुरू करने का लक्ष्य है।

इसके बाद साहिबाबाद से मोदीनगर और वर्ष 2025 में मेरठ से दिल्ली के बीच रैपिड ट्रेन का परिचालन यात्रियों के लिए किया जाएगा। साहिबाबाद से दुहाई के बीच पांच स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनका सिविल निर्माण कार्य अंतिम दौर में है।

कारिडोर के डेढ़ किलोमीटर के क्षेत्र में मिश्रित होगा लैंडयूज

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि रैपिड ट्रेन के कारिडोर के आसपास का डेढ़ किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र होगा। जिसमें लैंडयूज मिश्रित होगा। जिसके तहत जमीन पर औद्योगिक और आवासीय गतिविधि एक साथ की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि जिले में निवेश के लिए आठ हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य शासन से मिला था, लेकिन वर्तमान में 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए प्रस्ताव आ चुके हैं। निवेश के रफ्तार की मुख्य वजह जिले में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होना, रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य चलना और एनएच-नौ, डीएमई बनने से आसपास के शहरों और राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर होना है।

जिले के दस बड़े निवेशक

नाम - धनराशि

इंफोटच टेक्नालाजी प्राइवेट लिमिटेड - 12,500 करोड़ रुपये

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड - 11,472 करोड़ रुपये

ग्रुपेक्स नेटवर्क - 10,000 करोड़ रुपये

पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड - 5,700 करोड़ रुपये

उप्पल चड्ढा हाइटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड - 3,150 करोड़ रुपये

प्रतीक रिएलटर्स प्राइवेट लिमिटेड - 2,600 करोड़ रुपये

प्रतीक ग्रुप - 2,600 करोड़ रुपये

सनसिटी हाइटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड - 2,000 करोड़ रुपये

निद्धया टेक्सटाइल - 1,620 करोड़ रुपये

आर्टिशन - 1,400 करोड़ रुपये

गाजियाबाद। विदेश से आ रहे लोगों की कोरोना जांच गाजियाबाद में शुरू नहीं हो पाई है। हो भी तो कैसे जब स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसे लोगों की सूची ही नहीं है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर कोरोना जांच का कोई इंतजाम भी नहीं किया गया है। लापरवाही सिर्फ इतनी ही नहीं है। दो महीने से नमूनों की जिनोम सिक्वेसिंग भी नहीं कराई जा रही है। सरकारी अस्पतालों के वाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में लगने वाली मरीजों की लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की व्यवस्था भी नहीं की गई है।

विदेश से आ रहे लोगों के बारे में ब्योरा तैयार करने का काम 10 माह से बंद है। जनवरी तक उनका यात्रा विवरण तैयार किया जा रहा था। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि विदेश से आने वाले लोगों की सूची लखनऊ एयरपोर्ट ऑथोरिटी से मिलती है। यह नहीं मिल रही है। ऐसे लोगों को सात दिन के लिए आइसोलेट किया जाता है। जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए पहले सैंपल लखनऊ भेजे जाते थे लेकिन अब यह जांच नोएडा में ही हो जाएगी। सीएमओ ने बताया कि नोएडा जिम्स में इस बार सैंपल की जांच होगी, जिससे जल्द ही रिपोर्ट मिल जाएगी।

27 को सभी जगहों पर होगी मॉकड्रिल

कोरोना की रोकथाम के लिए इंतजाम पूरे हैं या नहीं इसके लिए 27 दिसंबर को जिले में मॉकड्रिल कराई जाएगी। मरीज को कितनी जल्दी उपचार मिला, दवाओं से लेकर उपचार की स्थिति का जायजा मॉकड्रिल के जरिए लिया जाएगा।

ट्रॉनिका सिटी से तीन किशोरियों को कराया बंधनमुक्त, एक

साइबर जालसाज ट्विटर और गूगल पर नजर गढ़ाए हुए हैं। जालसाजों ने रेलवे टिकट रिफंड के लिए ट्विटर पर शिकायत करने पर एक युवक से 95 हजार रुपये ठग लिए। इसके अलावा पेंशन रुकने पर कस्टमर केयर पर कॉल कर आरोपियों ने 75 वर्षीय रिटायर्ड जनरल मैनेजर से 98,924 रुपये ठग लिए। दोनों मामलों में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पूर्वांचल हाइट्स सोसाइटी निवासी 75 वर्षीय जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि वह एक कंपनी से जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत हुए थे। उनकी पेंशन किसी वजह से रुक गई थी। इसके चलते उन्होंने गूगल से ईपीएफ दफ्तर का नंबर लेकर कॉल की। उनके मोबाइल पर बाद में कॉल आई। कॉलर ने उनसे पेंशन शुरू कराने का झांसा देकर डेबिट कार्ड की फोटो कॉपी मांग ली। इसके बाद आरोपी अन्य निजी जानकारी भी हासिल कर उनके खाते से दो बार में 98924 रुपये निकाल लिए। इसकी शिकायत बैंक अधिकारियों को देकर उन्होंने डेबिट कार्ड आदि को ब्लॉक कराया और पुलिस को शिकायत दी। इधर, डेल्टा-1 निवासी सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने आईआरसीटीसी के एप से टिकट बुक कराई थी। लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाई और उनके खाते से रुपये कट गए। रिफंड के लिए उन्होंने ट्वीट किया। साइबर ठगों ने उनसे संपर्क कर रिफंड वापस दिलाने का झांसा दिया और निजी जानकारी हासिल कर उनके खाते से 95 हजार रुपये निकाल लिए। साइबर सेल की जांच के बाद अब सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये बरतें सावधानी

ट्विटर पर शिकायत करते समय मोबाइल नंबर आदि शेयर न करें।

गूगल से लिए गए नंबर की जांच करने के बाद ही डायल करें।

अनजान व्यक्ति की कॉल आने पर निजी जानकारी शेयर न करें।

अनजान व्यक्ति के भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें।

इनसाइड

MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, पुलिस ने घोषित किया था ईनाम

नोएडा की पुलिस ने एमबीबीएस में दाखिला दिलाने की नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह दर्जनों छात्रों से MBBS में प्रवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की है।

नोएडा। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने का झांसा देकर दर्जनों छात्रों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के तीन शातिर ठगों को सोमवार को सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए तीनों शातिरों पर डीसीपी नोएडा की ओर से 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। आरोपितों की पहचान बिहार के औरंगाबाद के नीरज कुमार सिंह, पटना के अभिषेक आनंद और दिल्ली के मालवीय नगर के मोहम्मद जुबेर के रूप में हुई है। नीरज गिरोह का सरगना है। गिरोह के तीन अन्य आरोपितों को कोतवाली पुलिस की टीमें पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी हैं। आरोपितों के कब्जे से 19 लाख रुपये की नकदी, सोने की छह चेन, छह अंगूठी, सोने और चांदी के अन्य आभूषण, छह मोबाइल, तीन डायरी, पेन कार्ड, आधार कार्ड और चार एटीएम बरामद हुआ है। गिरोह के सरगना नीरज के खिलाफ दिल्ली, बिहार और नोएडा के अलग-अलग कोतवाली में विभिन्न धाराओं में कुल छह मुकदमे दर्ज हैं। अभिषेक आनंद के खिलाफ चार और जुबेर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है।एडिशनल डीसीपी विशाल पांडेय ने बताया कि गिरफ्त में आए आरोपितों का लंबा आपराधिक इतिहास है,ऐसे में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें बीते एक माह से तीन राज्यों के सात शहरों में दबिश दे रही थीं। सूचना पर आरोपितों को सेक्टर-62 गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आरोपितों ने सेक्टर-63 के डी ब्लाक में कैरियर जंक्शन नाम की एक कंपनी खोली थी। कंपनी में बैठकर जालसाज ऐसे छात्रों का डाटा निकालते थे,जिन्होंने नीट की परीक्षा दी हो, लेकिन उत्तीर्ण नहीं हुए हैं।

नोएडा की सबसे ऊंची बिल्डिंग सुपरनोवा के 43वें फ्लोर से दिल्ली के शख्स ने दी जान, पहले भी हुई है ऐसी घटना

नोएडा की सबसे ऊंची इमारत सुपरटेक सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से दिल्ली के एक शख्स ने कथित तौर कूदकर जान दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शख्स प्रॉपटी कंसल्टेंट है।

नई दिल्ली। नोएडा की सबसे ऊंची इमारत सुपरटेक सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से गिरने के बाद दिल्ली के एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की कथित तौर पर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 43वीं मंजिल से प्रॉपटी कंसल्टेंट की गिरने से मौत हो गई।

नोएडा की सबसे ऊंची इमारत

पुलिस ने कहा कि यह घटना शनिवार को हुई जब 43 वर्षीय सलाहकार ने सेक्टर 94 में सुपरटेक सुपरनोवा बिल्डिंग का दौरा किया। 175 मीटर ऊंची यह इमारत नोएडा की सबसे ऊंची इमारत है। यह एक आवासीय-सह-व्यावसायिक स्थान है जिसकी ऊपरी मंजिलें अभी भी निर्माणाधीन हैं।

मौके पर शख्स की हुई मौत

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ₹पीड़ित उत्तर पश्चिम दिल्ली के रानी बाग इलाके में रहता था। सुपरनोवा इमारत में एक संपत्ति देखने आया था। ऐसा संदेह है कि उसने इमारत की 43वीं मंजिल से छलांग लगा दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।₹

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि कंसल्टेंट ने एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से मुलाकात की थी और साथ में बिल्डिंग का दौरा किया था। हालांकि, घटना के समय वह 43वीं मंजिल पर अकेला था क्योंकि ब्रोकर इमारत के भूतल पर आ गया था। अधिकारी ने कहा कि सेक्टर 126 थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पहले भी ऐसी हुई इस तरह की घटना

बता दें कि इससे पहले सेक्टर-58 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर-62 स्थित इरोज अपार्टमेंट में रहने वाली एक महिला ने बुधवार तड़के पांचवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। जांच में सामने आया है कि महिला तनाव में थी और कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में उसका लंबे समय से उपचार चल रहा था।

यहीं नहीं इसके अलावा पिछले साल नवंबर महीने में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक महिला ने 16 वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उस दौरान घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। आत्महत्या करने वाली 35 वर्षीय महिला पीएचडी कर रही थी।

गाजियाबाद की एलिवेटेड रोड पर कार खड़ी कर युवती ने बनाई रील, कटा 17 हजार का चालान

गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रील बनाना एक युवती को भारी पड़ गया। मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर युवती का 17 हजार रुपये का चालान कर रिपोर्ट दर्ज की गई। मामला साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र का है।

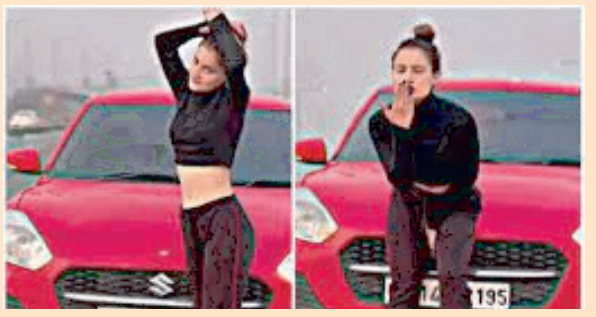

गाजियाबाद। साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर एक युवती ने कार खड़ी करके रील बनाई। उसका वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो गया। यातायात पुलिस ने कार का 17 हजार रुपये का चालान काटा। साहिबाबाद कोतवाली में कार नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज हुई। रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। 16 मिनट के वीडियो में दिख रहा है कि लाल कार एलिवेटेड रोड पर खड़ी है। एक युवती उसके सामने खड़ी होकर वीडियो बना रही है। सड़क पर वाहनों तेज गति से दौड़ रहे हैं। हादसे का खतरा बन रहा है।

11 वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा

वीडियो को संज्ञान में लेकर साहिबाबाद कोतवाली पुलिस ने कार नंबर के आधार पर युवती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। यातायात पुलिस ने उसका 17 हजार रुपये का चालान काटा। सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद पूनम मिश्रा ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ट्रॉनिका सिटी से तीन किशोरियों को कराया बंधनमुक्त, एक ओडिशा और दो बंगाल की रहने वाली

ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के विजय विहार में रविवार को पुलिस ने एक एनजीओ की सहयोग से तीन किशोरियों को बंधनमुक्त कराया। इनमें दो किशोरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और एक किशोरी ओडिशा की रहने वाली है।

गाजियाबाद। ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के विजय विहार में रविवार को पुलिस ने एक एनजीओ की सहयोग से तीन किशोरियों को बंधनमुक्त कराया। इनमें दो किशोरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और एक किशोरी ओडिशा की रहने वाली है। इनको प्लेसमेंट एजेंसी संचालक ने एक मकान में बंधक बनाकर रखा हुआ था। पुलिस ने तीनों किशोरियों को रेस्क्यू कर केयर होम में भेज दिया है।

मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी के मेटली पुलिस थाने में एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस किशोरी को मेटली में ही रहने वाला एक किशोर प्रेम प्रसंग के नाम पर बहलाकर लाया था। उसके मोबाइल की लोकेशन गाजियाबाद में दिख रही थी।

मेटली पुलिस ने उनके एनजीओ से संपर्क कर मदद मांगी। उन्होंने इसकी जानकारी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डा. सुचिता चतुर्वेदी को दी। डॉ. सुचिता के साथ वह ट्रॉनिका सिटी के विजय विहार पुलिस चौकी पहुंचे। जिस स्थान पर किशोरी की लोकेशन थी वहां पर उन्होंने पुलिस की टीम के साथ कई मकानों की तलाश ली। वह एक किशोरी को रेस्क्यू करने गए थे लेकिन वहां पर एक मकान में उसके दो और किशोरियों को बंधक बनाकर रखा गया था।

पुलिस के आने की लग गई थी भनक

ओडिशा निवासी प्लेसमेंट संचालक अजीत ने किराये पर मकान ले रखा था। उसे पुलिस के आने की भनक लग गई थी। वह पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया। अजीत की पत्नी घर पर मिली थी। पुलिस ने उसकी पत्नी से भी पूछताछ की है। गाजियाबाद पुलिस ने मेटली की पुलिस को इसकी सूचना दे दी है।

घरेलू सहायिका का दिलाता था काम

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपित पश्चिम बंगाल और ओडिशा से किशोरियों नौकरी का लालच देकर लाता था। वह दिल्ली एनसीआर में घरेलू सहायिका का काम कराता था। आरोपित का ओडिशा और पश्चिम बंगाल में नेटवर्क फैला हुआ है।

किशोर को भेजा गया बाल सुधार गृह

जो किशोर बहला-फुसलाकर किशोरी को लाया था, उसकी उम्र 17 साल है। किशोर भी नौकरी के चक्कर में प्लेसमेंट एजेंसी संचालक के चक्कर में फंस गया था। किशोर को भी आरोपित ने नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। पुलिस ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है। पुलिस यौन शोषण के एंगल से भी जांच कर रही है।

एक एनजीओ की टीम ने पुलिस चौकी पर पहुंचकर मदद मांगी थी। पुलिस ने उनकी मदद के लिए साथ गई थी। जांच की जा रही है। - रजनीश उपाध्याय, सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी

इनसाइड

क्या होता है FASTag और कैसे करें इसका बैलेंस चेक, जानें पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप

रोड पर जब आप अपनी कार को लेकर चलते हैं तो आपको टोल टैक्स भरना होता है।आज के समय में FASTag की मदद से चंद मिनट में आप टोल टैक्स भर देते हैं। क्या आप जानते हैं इसका रिचार्ज कैसे होता है और इसमें बैलेंस का पता कैसे करते हैं।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने टोल को लेकर कई नियम बनाए हुए है। रोड पर गाड़ी चलाते वक्त टोल टैक्स देने के बारें में आप तो जानते ही होगे। पहले आपको लंबे समय तक लाइन में लगकर टोल देना पड़ता था । लेकिन अब जमाना टेक्नोलॉजी का है इस समय के दौर में अब लोग टोल टैक्स FASTag की मदद से चंद मिनट में भर देते हैं। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है ? इसका रिचार्ज कैसे करते हैं और इसका बैलेंस कैसे चेक करते हैं।

FASTag क्या है ?

FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये टैग अधिकृत बैंक द्वारा किया जाता है और ऑनलाइन माध्यम से इसे टोल लिया जाता है। इसके उपयोग के कारण आप टोल टैक्स पर लंबे समय में लाइन में लगे बिना ही टोल चूका देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर लगे रीडर्स कार की विंडस्क्रीन पर चिपकाए गए टैग को स्कैन करते हैं और लिंक किए गए अकाउंट के माध्यम से चार्ज कट जाता है।

ऑनलाइन कैसे करें रिचार्ज

भले ही लोग इसको काफी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोगों को इसके रिर्जाज प्रक्रिया के बारें में नहीं जानते हैं। इसको रिचार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ,फास्टैग जारी करने वाले बैंक की वेबसाइटों पर भुगतान और पेटीएम के माध्यम से आप ऑनलाइन रिर्चाज कर सकते हैं।

कैसे करें बैलेंस चेक

सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके बाद फास्टैग अकाउंट को लॉग इन करें।

इसके बाद फास्टैग अकाउंट के बैलेंस चेक करने के ऑप्शन पर जाए।

आपको बैलेंस दिखाई दे जाएगा।

साल 2022 में गाड़ियों के रहे ये टॉप 5 ट्रेंडिंग फीचर्स

नए साल के आने में अब कुछ ही दिन बाकी है। इसके साथ ही इस साल कई ऐसे फीचर्स आए हैं जो कार में लोगों द्वारा सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं।आज हम आपके लिए टॉप 5 ट्रेंडिंग फीचर्स की लिस्ट लेकर आए हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में इस साल कई गाड़ियां लॉन्च हुई है। इसके साथ ही नए साल के आने में अब कुछ ही दिन बाकी है। आज हम आपके लिए गाड़ियों के उन फीचर्स की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें सबसे अधिक पसंद किया जाता है। आज हम आपके लिए टॉप 5 ट्रेंडिंग फीचर्स की लिस्ट लेकर आए हैं।

HUD display

2022 में हमने Maruti Suzuki Baleno से लेकर BYD Atto 3 इलेक्ट्रिक SUV तक हमने HUDs को 2022 लॉन्च हुई अधिकांश कारों में देखा है। हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी) एक और बनावट विशेषता है जो खरीदारों और निर्माताओं दोनो पर अच्छी -खासी पकड़ बनाता है। इसको सबसे अधिक लोगों द्वारा पसंद किया जाता है।

Ventilated seats

पिछले कुछ सालों में इस सीट का क्रेज सबसे अधिक देखा गया है। कार को सेलेक्ट करते समय लोग इस सीट को सबसे अधिक खोजते हैं। इन दिनो वाहन निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों में इस सीट को दे रहे हैं। इसको हमने कई गाड़ियों जैसें- Tata Nexon EV, Toyota Hyryder, VW Virtus में देखा है।

क्या सच में गायब हो जाएंगी पेट्रोल कारें? EV या हाइड्रोजन; कौन बनेगा ऑटोमोबाइल का भविष्य

Petrol Car की जगह लेने के लिए कंपनियां तेजी के साथ इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कारों को पेश कर रही हैं। ऐसे में क्या सच में इस तरह की गाड़ियां की भविष्य में मिलेंगी इस बात से पहले इनके फायदे और नुकसान को समझ लें।

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ ICE इंजनों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इन्ही कारणों से वाहन निर्माता कंपनियां ईंधन के नए विकल्पों की तलाश कर रही हैं। बीते कुछ साल में विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन खूब बढ़ा है। यह सस्ता और कम नुकसानदायक विकल्प है। वहीं, अब एक नया हाइड्रोजन विकल्प भी सामने आया है।

हाल में हुए Auto Expo 2023 में MG Motors ने अपनी हाइड्रोजन कार Euniq 7 को पेश किया, जो हाइड्रोजन सेल के अलावा कई और खूबियों से लैस थी। वहीं, Toyota ने पहले ही अपनी Mirai कार के कॉन्सेप्ट वर्जन को पेश कर दिया है।

इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन दोनों ही गाड़ियों को भविष्य की गाड़ी के रूप में देखा जा रहा है और ये दोनों ही पेट्रोल कारों की जगह ले सकती है। पर सवाल उठता है कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक दोनों में से कौन-सी कार ज्यादा सस्ती, टिकाऊ और भरोसेमंद साबित होगी ? इसलिए, आज हम इन दोनों की एक तुलना करने जा रहे हैं।

कौन-सी कार में मिलेगी ज्यादा रेंज

इसमें कोई शक नहीं है कि हाइड्रोजन कारों में रेंज ज्यादा मिलने वाली है। हाइड्रोन कारों का धनत्व ज्यादा होता है, जिससे ये कारें दूर तक चलाई जा सकती है। वर्तमान में पेश किए गए मॉडलों के आधार पर टोयोटा मिराई को एक बार चार्ज करने पर 600 किमी तक की रेंज दे सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों में अब तक अधिकतम 250 किमी तक की रेंज देखई गई है।

बजट फ्रेंडली

ज्यादा रेंज के साथ ही गाड़ियों को बजट फ्रेंडली भी होना जरूरी है। इस आधार पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक मिडिल क्लास फैमिली के बजट में ज्यादा आसानी से आ सकती है, जबकि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों में लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से इनकी कीमतें भी अधिक होंगी। वहीं, बाद के समय में कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन कारों को कम कीमत पर लाना होगा।

रिफिल में लगने वाला समय

इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन दोनों गाड़ियां को अगर पेट्रोल गाड़ियों की जगह लेनी है तो इसे रिफिल करने में कम समय लगना चाहिए। एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक कारों अगर एक बार डिस्चार्ज हो गई तो इसे फुल चार्ज होने में 4 से 8 घंटे का समय लगता है। वहीं, हाइब्रिड कारों में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। फ्यूल स्टेशन पर एक किलो हाइड्रोजन को रिफिल करने में बस 5 से 10 मिनट कसमी लगता है, जो काफी हद तक पेट्रोल रिफिलिंग के समान ही है।

Auto Expo 2023: टॉप ब्रांड्स की गाड़ियां भा रही हैं, अभी तक नहीं गये तो हो आइये और देखिये गाड़ियों के शानदार नजारे

ऑटो एक्सपो 2023 में कई गाड़ियां अनविल होने वाली हैं। इसमें Maruti Suzuki Hyundai Tata Motors Mahindra Toyota Kia MG Renault और Nissan जैसी प्रमुख ऑटो निर्माता कंपनियों से इस कार्यक्रम में कुछ शानदार कॉन्सेप्ट कारों और उत्पादन के लिए तैयार मॉडल प्रदर्शित करने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। ऑटो एक्सपो भारत में सबसे बड़ा ऑटोमोटिव इवेंट है, जो हर दो साल में होता है। इस इवेंट का आयोजन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा किया जाता है। इस एक्सपो में नई कारों, नई बाइक्स, नई स्कूटर, कॉन्सेप्ट गाड़ियों, कॉमर्शियल वाहनों समेत कई टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता है। हालांकि, 2022 में होने वाले इस इवेंट को कोविड-19 के चलते रद्द किया गया था। लेकिन अब यह एक्सपो जनवरी 2023 में फिर से लौटने के लिए तैयार है।

ऑटो एक्सपो 2023: स्थान

ऑटो एक्सपो 2023 इवेंट के पिछले कुछ संस्करणों की तरह इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जाएगा। इंडिया एक्सपो मार्ट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेपी गोल्फ कोर्स के पास स्थित है। इसके साथ ही दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो-कंपोनेंट शो, जो ऑटो कंपोनेंट इंडट्री द्वारा आयोजित किया जाएगा।

ऑटो एक्सपो 2023: तारीख और समय

ऑटो एक्सपो 2023 13 से 18 जनवरी 2023 तक चलेगा। समय की बता करें तो 14 और 15 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक, 16 और 17 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक , 18 जनवरी को सुबह 11 बजे से लेकर 6 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश बंद होने के समय से एक घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा, जबकि प्रदर्शनी हॉल में प्रवेश हर दिन बंद होने के समय से 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा।

Auto Expo 2023 में कैसे जाएं

इंडिया एक्सपो मार्ट दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अन्य हिस्सों के साथ सड़कों और मेट्रो रेल नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहां आठ लेन ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के माध्यम से मध्य दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा, मेट्रो रेल और व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से स्थल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। दावा किया जाता है कि इस स्थल में लगभग 8,000 वाहनों की पार्किंग क्षमता है।

ऑटो एक्सपो 2023 में ये ब्रांड कर रहे भागीदारी

ऑटो एक्सपो 2023 में कई गाड़ियां अनविल होने वाली हैं। इसमें Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors, Mahindra, Toyota, Kia, MG, Renault, और Nissan जैसी प्रमुख ऑटो निर्माता कंपनियों से इस कार्यक्रम में कुछ शानदार कॉन्सेप्ट कारों और उत्पादन के लिए तैयार मॉडल प्रदर्शित करने की उम्मीद है। इस समारोह में मर्सिडीज-बेंज, जगुआर लैंड रोवर और बीएमडब्ल्यू जैसे लग्जरी कार ब्रांड के भी मौजूद रहने की उम्मीद है।

इंडियन मार्केट में कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स क्यों फेमस? असल वजहों के बारे में समझें

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहां बेचे गए कुल वाहनों की अधिकांश बिक्री पैसेंजर वाहनों द्वारा कवर की जाती है और उनमें से एक बड़ा हिस्सा दोपहिया वाहनों का हैं। कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स को लोग अधिक महत्व देते हैं।

नई दिल्ली। भारत में इस समय कारों की बिक्री में इजाफा देखने को मिला है। आप खुद ही आप पास के घरों में खड़ी कारों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि, जिनके भी घर कार होगी उनके घर दोपहिया वाहन जरूर देखने को मिलेगा। इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं उन 3 वजहों के बारे में जहां आपको यह पता चलेगा कि कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स इंडियन मार्केट में क्यों फेमस हैं

बेहतरीन माइलेज

कारों की तुलना में मोटरसाइकिल की माइलेज भी अधिक होती है। अगर कार औसतन 25 की माइलेज देती है तो टू-व्हीलर भी 60-70 तक की औसतन माइलेज देने में सक्षम है। यही वजह है कि भारत में अधिकतर लोग चार पहिया की तुलना में दोपहिया वाहन खरीदना अधिक पसंद करते हैं। इस समय एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस आने वाली मोटरसाइकिलों जिसमें अधिक सीसी का इंजन लगा हुआ होता है उसकी औसतन माइलेज 20-30 Kmpl होती है।

प्रदूषण

पर्यावरण के नजरिए से भी दोपहिया वाहन चार पहिया वाहन की तुलना में बेहतरीन होते हैं, क्योंकि चार पहिया वाहन अधिक ईंधन खाते हैं और उससे अधिक पॉल्यूशन भी निकलता है, वहीं दोपहिया वाहन हैं बहुत कम ईंधन खर्च होने के कारण उससे होने वाली पॉल्यूशन की मात्रा कम होती है। इसलिए, पर्यावरण के लिहाज से टू-व्हीलर बेस्ट होती हैं।

किफायती दाम

दोपहिया वाहन कार की तुलना में बेहद सस्ते होते हैं। जिस वजह से एक मध्यम वर्गीय परिवार और निचला मध्यम वर्गीय परिवार भी इसे खरीद पाता है। भारत के बाज़ार में लगभग 40,000 रुपए की शुरुआती क़ीमत से दोपहिया वाहनों की बिक्री शुरू हो जाती है। इसके अलावा, इन वाहनों के लिए बीमा बहुत कम लागत पर आता है। दोपहिया वाहनों की सबसे ख़ास बात यह होती है कि इनकी री सेल क़ीमत भी बहुत अधिक होती है। साथ ही इनका माईलेज भी कार की तुलना में कहीं बेहतर होता है।

इस मौसम में सबसे अधिक परेशान करती है कार के अंदर की धुंध, इन उपायों से मिलेगा चुटकियों में समाधान

आपके ड्राइविंग अनुभव को धुंधली स्क्रीन काफी हद तक खराब कर देती है। इससे गाड़ी चलाते समय सामने देखना काफी मुश्किल हो जाता है। धुंध सिर्फ बाहर ही नहीं आपके कार के अंदर भी परेशान करती है। इसके लिए आपको इन चुनिंदा बातों का ख्याल रखना चहिए।

नई दिल्ली। इस समय ठंड काफी तेजी से बढ़ रही है।सुबह के समय कोहरा काफी अधिक हो रहा है, जिससे गाड़ी चलाते समय सामने देखना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये परेशानी कार के अंदर भी होती है। अगर आपके कार के अंदर भी ठंड के मौसम में धुंध भर जाती है तो आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिससे आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके ड्राइविंग अनुभव को धुंधली स्क्रीन काफी हद तक खराब कर देती है। सबसे अधिक दिक्कत इस समय होती है। कोहरे के कारण आप कार के बाहर का देख नहीं सकते हैं। धुंध सिर्फ बाहर ही नहीं आपके कार के अंदर भी परेशान करती है। इसके लिए आपको इन चुनिंदा बातों का ख्याल रखना चहिए।

डिफॉग बटन का इस्तेमाल करें

अगर आप इस बात से अनजान हैं तो अपनी कार के अंदर आप विंडशील्ड को डिफॉग करने के लिए गाड़ी के अंदर दिए गए डिफॉग बटन का इस्तेमाल करें। ये बटन आपके कार के अंदर आता है। इसको दबाने के बाद हवा सीधे विंडशील्ड तक पहुंच जाती है।

एसी को ऑन करें

कार में जैसे ही बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद फॉग महसूस होने लगता है, जिसके कारण आप बाहर का देख नहीं सकते और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसके लिए आप कार में एसी को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद लिंट-फ्री कपड़े से स्क्रीन को पोछ लेना चाहिए, ताकि आपको दिखाई देने लगे। इसके कारण कार के अंदर की धुंध भी गायब हो जाती है।

खिड़की को नीचे करें

कार के अंदर से धुंध को बाहर करने के लिए खिड़की को नीचे करना एक अच्छा ऑप्शन है। इससे बाहर की हवा अचानक आपकी कार के अंदरुनी हिस्सो को भर देती है, इसके कारण ही अंदर का तापमान बाहर के तापमान की तरह हो जाता है।

गरीबों के सशक्तिकरण का अध्याय

डा. जयंतीलाल भंडारी

एक जनवरी से नए वर्ष 2023 में वर्षभर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाली देश की दो-तिहाई आबादी यानी करीब 81.35 करोड़ लोगों को राशन प्रणाली के तहत मुफ्त में अनाज देने की नई पहल दुनिया भर में रेखांकित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक सरकार ने 2023 में वर्षभर गरीबों की खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त अनाज वितरण का निर्णय लिया है।

देश में गरीबी, कुपोषण और भूख की चिंताएं कम करने के लिए इस क्षेत्र की ओर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीआरआर) व्यय का प्रवाह बढ़ाकर भी बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी तथा कुपोषण की पीड़ाओं से राहत दी जानी होगी। हम उम्मीद करें कि नए वर्ष 2023 में कोरोना के नए संक्रमण तथा वैश्विक मंदी की चुनौती के बीच केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में वर्ष भर राशन प्रणाली के तहत देश के गरीब व कमजोर वर्ग के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज दिए जाने का निर्णय गरीबों के कल्याण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे कमजोर वर्ग के करोड़ों लोगों को महंगाई और मंदी की चुनौती से बचाते हुए गरीबी के नए दलदल में फंसने से बचाया जा सकेगा'

एक जनवरी से नए वर्ष 2023 में वर्षभर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाली देश की दो-तिहाई आबादी यानी करीब 81.35 करोड़ लोगों को राशन प्रणाली के तहत मुफ्त में अनाज देने की नई पहल दुनिया भर में रेखांकित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक सरकार ने 2023 में वर्षभर गरीबों की खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त अनाज वितरण का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि देश में राशन प्रणाली के तहत प्रत्येक सामान्य उपभोक्ता को हर महीने पांच किलो की दर से अनाज वितरित किया जाता है, जबकि अंत्योदय वर्ग के उपभोक्ताओं को अनाज की यह मात्रा सात किलो प्रति व्यक्ति होती है। यानी प्रत्येक सामान्य परिवार को 25 किलो और अंत्योदय वर्ग के परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाता है। अब तक जहां तीन रुपए प्रति किलो की दर से चावल, दो रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपए प्रति किलो की दर से मोटा अनाज दिया जाता है। अब राशन कार्डधारक उपभोक्ताओं को सस्ती दर की राशन दुकानों पर कोई भुगतान नहीं करना होगा। ज्ञातव्य है कि सरकार ने पिछले करीब ढाई वर्ष से चली आ रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत पांच किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिए जाने की योजना खत्म कर दी है। यद्यपि सरकार के इस निर्णय से केंद्र सरकार के खजाने पर दो लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा, लेकिन इस नई व्यवस्था से जहां गरीबों की खाद्य सुरक्षा निश्चित होगी, वहीं खाद्य सुरक्षा व गरीबी कल्याण योजना को एक किए जाने से सब्सिडी में बचत होगी। साथ ही खाद्यान्न भंडार में अतिरिक्त अनाज की मौजूदगी बाजार में खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित करते हुए दिखाई दे सकेगी। उल्लेखनीय है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ-साथ वैश्विक मंदी और अब चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोहराम मचा रहे ओमिक्रान बीएफ.7 के कारण वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं से गरीबों के कल्याण की चुनौती और बढ़ गई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती गरीबी पर प्रकाशित हो रही विभिन्न रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि कोरोना काल के कारण निर्मित भारत में गरीबी, बेरोजगारी तथा मानव विकास सूचकांक में गिरावट का असर अभी भी बना हुआ है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 189 देशों की सूची में भारत 132वें पायदान पर पाया गया है। पिछले वर्ष 2021 में प्रकाशित इस सूचकांक में भारत 131वें पायदान पर था। यद्यपि पिछले दशक में देश में जिस तेजी से गरीबी और भूख की चुनौती में कमी आ रही थी, उसे अकल्पनीय कोरोना संकट ने बुरी तरह प्रभावित किया है।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रकाशित दि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दि वर्ल्ड रिपोर्ट-2022 के अनुसार 2004 में भारत की 24 करोड़ आबादी कुपोषित थी, यह संख्या घटते हुए 2021 में 22.4 करोड़ पर पहुंच गई है। देश में मानव पूंजी के निर्माण में कोरोना महामारी ने जोखिम बढ़ाई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विगत 6 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए तथा केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक जिस तरह मुफ्त अनाज पहुंचाया है, वह व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। निश्चित रूप से पूर्व में भी कोविड-19 के बीच गरीबों को महंगाई और भूख की चुनौती से बचाने के लिए भारत में अपनाई गई मुफ्त अनाज वितरण की प्रभावी पहल को दुनियाभर में रेखांकित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के द्वारा प्रकाशित रिसर्च पेपर में कोविड की पहली लहर 2020-21 के प्रभावों को अध्ययन में शामिल करते हुए कहा गया है कि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम से लॉकडाउन के प्रभावों तथा महंगाई की गरीबों पर मार कम हुई। डिजिटल हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गरीब लोगों की मुठ्ठियों में मुफ्त खाद्यान्न सौंपकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट दी जा सकी है। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि देश में आम आदमी के कल्याण के लिए लागू की गई विभिन्न सरकारी योजनाएं मसलन पीएमजीकेवाई, सामुदायिक रसोई, वन नेशन वन राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत पोषण अभियान, समग्र शिक्षा जैसी योजनाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी के स्तर में कमी और स्वास्थ्य व भुखमरी की चुनौती को कम करने में सहायक रही हैं।

यदि हाल ही के वर्षों में सरकार के ऐसे विशिष्ट सफल अभियान नहीं होते तो देश में गरीबी, भूख, स्वास्थ्य के क्षेत्र की चुनौतियां और बढ़ी हुई दिखाई देती। निश्चित रूप से तेजी से बढ़ती खाद्यान्न कीमतों के मद्देनजर गरीबों को मुश्किलों से बचाने और खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता हेतु अभी बहुत अधिक कारगर प्रयासों की जरूरत बनी हुई है। देश में बहुआयामी गरीबी, बेरोजगारी, भूख और कुपोषण खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा घोषित नई जनकल्याण योजनाओं, स्वरोजगार योजनाओं, कौशल विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक रसोई व्यवस्था तथा पोषण अभियान-2 को पूरी तरह कारगर व सफल बनाया जाना होगा। मोटे अनाज का उत्पादन और वितरण बढ़ाकर देश में भूख और कुपोषण की चुनौती का सामना करके गरीबों की कार्यक्षमता बढ़ाना होगी। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं-चावल की बजाय मोटे अनाज दिए जाने से भूख और कुपोषण की चुनौती से मुकाबला किया जाना होगा। चूंकि खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार भारत में उत्पादित लगभग 40 फीसदी भोजन हर साल बर्बाद हो जाता है, ऐसे में देश में भोजन की बर्बादी को बचाना होगा। देश में गरीबी, कुपोषण और भूख की चिंताएं कम करने के लिए इस क्षेत्र की ओर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीआरआर) व्यय का प्रवाह बढ़ाकर भी बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी तथा कुपोषण की पीड़ाओं से राहत दी जानी होगी। हम उम्मीद करें कि नए वर्ष 2023 में कोरोना के नए संक्रमण तथा वैश्विक मंदी की चुनौती के बीच केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में वर्ष भर राशन प्रणाली के तहत देश के गरीब व कमजोर वर्ग के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज दिए जाने का निर्णय गरीबों के कल्याण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे कमजोर वर्ग के करोड़ों लोगों को महंगाई और मंदी की चुनौती से बचाते हुए गरीबी के नए दलदल में फंसने से बचाया जा सकेगा।

संपादक की कलम से

एक असंवैधानिक युद्ध!

एक लंबे वक्त से दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री केजरीवाल और 'आप' के नेताओं, सांसदों के बीच पत्र-युद्ध और बयान-युद्ध जारी है। कई बार यह अनैतिक और अभद्र भी महसूस हुआ। दोनों पक्ष खुन्नस से भरे प्रतीत होते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पार्टी 'आप' को चुनावी जनादेश हासिल है। वे राजधानी दिल्ली की 2 करोड़ से अधिक आबादी के निर्वाचित जन-प्रतिनिधि हैं। यही लोकतंत्र और संविधान है! व्यवस्था में उपराज्यपाल भी पदासीन हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संविधान में उपराज्यपाल और राज्य कैबिनेट की लक्ष्मण-रेखाएं स्पष्ट हैं, लेकिन उनकी व्याख्याएं मनमाफिक की जाती रही हैं। यदि उपराज्यपाल सर्वोच्च अदालत के फैसले को 'सलाह' मानते हैं, तो यह भी संविधान का घोर उल्लंघन है और अदालत की अवमानना भी है, लेकिन उपराज्यपाल ने खुद को 'वॉयसरॉय' का प्रतीक मान लिया है, क्योंकि लक्ष्मण-रेखा बार-बार लांघने के बावजूद उनके खिलाफ कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई कौन करेगा? भारत सरकार की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति कोई निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उपराज्यपाल तो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, लिहाजा दाल में बहुत कुछ काला लगता है! दरअसल यह राजनीति जानबूझ कर खेली जा रही है। सवाल यह है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बयान-युद्ध इतना सार्वजनिक हो चुका है कि संविधान और संवैधानिक पद शर्मसार हो रहे हैं।

क्या यह देश और उसकी व्यवस्थाओं को लांछित नहीं कर रहा है? मुख्यमंत्री केजरीवाल को गर्जना के स्वर में विधानसभा में सवाल करने पड़े कि यह उपराज्यपाल कौन है? क्या है? हमारे ऊपर थोप दिया गया है। क्या यह 'वॉयसरॉय' है? यह निर्वाचित सरकार को काम क्यों नहीं करने दे रहा? सिर्फ यही नहीं, मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों, विधायकों सहित सडक़ पर सार्वजनिक मार्च करते हुए 'राजभवन' तक क्यों जाना पड़ा और उपराज्यपाल ने मुलाकात करना भी मुनासिब नहीं समझा? यह भी संविधान का उल्लंघन है और हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर मोटा सवाल है। आखिर यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? यदि उपराज्यपाल के मनमाने फैसलों और कैबिनेट द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों की फाइलें लौटाने के कारण दिल्ली की जनता के हित प्रभावित होते हैं, तो वह लोकतंत्र-विरोधी है। सवाल उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों पर हैं। आखिर ऐसा कौन-सा अडियलपन है कि दोनों संवैधानिक चेहरे किसी भी मुद्दे पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं? सहज और सौहाद्र्र वाला संवाद ही नहीं है? उपराज्यपाल ने ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की है और सरकार भी उन्हीं के नाम पर काम करती है। गली-मुहल्ले के बच्चों की तरह यह लड़ाई लड़ी जा रही है! दिल्ली में जलापूर्ति प्रभावित हुई है। मोहल्ला क्लीनिक में न तो मेडिकल टेस्ट हो पा रहे हैं और न ही दवाएं उपलब्ध हैं। बुजुर्गों और महिलाओं की पेंशन रोकी जा रही है। शिक्षकों और छात्रों का मज़ाक उड़ाते हुए उन्हें 'भूत' कहा जा रहा है।

मुद्दों और लंबित फाइलों की सूची बहुत लंबी है। हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद और पार्टीजनों को उपराज्यपाल के प्रति अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को रोकें। संविधान की गरिमा और पवित्रता के लिए हर स्तर पर मर्यादा लाजिमी है। मुख्यमंत्री भी शिक्षकों को फिनलैंड भेजने की जिद छोड़ें। भारत की शिक्षा-व्यवस्था और नीतियां फिनलैंड के बिल्कुल विपरीत हैं।

इतिहास में आज

24 जनवरी का इतिहास

भारत के कोलकाता शहर में 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई।

1859 में 230 मीटर गहराई तक तेल के लिए खोदे गये कुएं से पहली बार तेल निकला।

बुखारेस्ट को 1862 में रोमानिया की राजधानी बनाया गया।

रूस में 1924 में पेट्रोग्राद का नाम बदलकर लेनिनग्राद कर दिया गया।

1936 को अलबर्ट सैरुएट फ्रांस के प्रधानमंत्री बने।

चिली में 1939 में आये भूकंप से लगभग 50 हजार लोग मरे।

संविधान सभा ने 1950 में राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना।

जन-गण-मन को 1950 में भारत के राष्ट्रगान का दर्जा मिला।

प्रेम माथुर 1951 में भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनीं।

बंबई में पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 1952 में हुआ।

आल्प्स की पहाड़ियों में 1966 में मोंब्लॉ के शिखर के पास एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान दुर्घटना में लगभग 120 लोगों की मौत हो गई।

नेवादा में परमाणु परीक्षण अमेरिका ने 1979 में किया।

पेरू में सोने की खान में 1989 में 125 से अधिक मजदूर फँस गये।

जापान ने 1990 में पहला लूनर प्रोब लॉन्च किया।

लिथुआनिया गणराज्य ने 1991 में सोवियत संघ के सैनिकों हटाने की मांग की।

1993 को सोयूज टी.एम. 16 प्रक्षेपित किया गया।

1996 को सं.रा. अमेरिका के इतिहास में पहली बार देश की प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया।

चुनावों में दलितों का आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाने हेतु संविधान के 79वें संशोधन को 2000 में राष्ट्रपति की मंजूरी।

भारतीय उपग्रह इनसेट-3सी सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में 2002 में स्थापित।

फ्रांस और भारत के बीच 2003 में प्रत्यर्पण संधि।

आंध्र प्रदेश के तेलगुदेशम के विधायक परिताला रवि की 2005 में गोली मारकर हत्या करा दी गयी।

मॉस्को के डोनोडिडोवो हवाई अड्डे पर 2011 में हुए बम विस्फोट से 40 लोगों की मौत, 200 घायल।

24 जनवरी को जन्मे व्यक्ति – Born on 24 January

जर्मनी के लेखक अर्नेस्ट हूफ़मैन का 1776 में जन्म हुआ।

फ्रांस के लेखक और कवि अलफ्रेड डो.वीनी का 1797 में जन्म हुआ।

प्रथम भारतीय बैरिस्टर ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर का 1826 में जन्म हुआ।

महान् स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का 1877 में जन्म हुआ।

जोशीमठ का हिमालय के लिए संदेश

हिमालयी राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार पर दबाव डाल कर पर्वतीय विकास के लिए अलग विकास मॉडल बनवाने का प्रयास करें और केंद्र सरकार एसजेड कासिम की अध्यक्षता वाली कमेटी की रपट का अध्ययन करके और वर्तमान में नीति आयोग द्वारा बनाए गए हिमालयी क्षेत्रीय परिषद को इस काम पर लगाना चाहिए और विश्वव्यापी अनुभवों के आधार पर पर्वतीय विकास का पर्यावरण मित्र मॉडल विकसित करना चाहिए'

जोशीमठ की त्रासदी ने पूरे देश को अचंभित ही नहीं किया है बल्कि हिमालय में विकास की गाड़ी की दिशा पर भी अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। सदियों पुराना शहर आखिर धंस क्यों रहा है। वैसे तो आजादी के बाद से ही हिमालय के लिए विकास योजना को इस क्षेत्र की भौगोलिक और पर्यावरण की विशिष्टता के कारण अलग दृष्टि से देखा जाने लगा था। इसी कारण योजना आयोग में भी हिमालय का अलग सेल हुआ करता था। अब नीति आयोग में भी हिमालयन क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है ताकि हिमालय की विशिष्ट नाजुक स्थिति को ध्यान में रख कर विकास गतिविधियों का खाका बनाया जा सके। 1992 में डा. एसजेड कासिम की अध्यक्षता में योजना आयोग ने हिमालय में विकास की दिशा और दशा को निर्धारित करने के लिए एक ग्रुप का गठन किया था जिसकी रपट 1992 में ही आ गई थी। किन्तु इस तरह की तमाम कोशिशों के बावजूद हिमालयी क्षेत्र में विकास के लिए कोई अलग मॉडल विकसित नहीं किया जा सका, जिसका मुख्य कारण यह रहा है कि हिमालयी संसाधनों पर तो योजनाकारों की नजर रही, किन्तु उनके दोहन या दोहन के तरीकों के कारण कितनी विपदाएं हमें घेर सकती हैं और देश के लिए हिमालय द्वारा की जा रही पर्यावरणीय सेवाओं पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इस ओर किसी ने नहीं सोचा। बातें तो हुई किन्तु जमीन पर कुछ उतर नहीं सका। इसी का नतीजा है कि हिमालय में मनमानी उखाड़ पछाड़ विकास के लिए की गई जो अब तक जारी है और कमेटियों या हिमालयी विकास को दिशा देने के लिए बनाए गए ग्रुपों की संस्तुतियां धूल फांक रही हैं। जो लोग हिमालय के साथ मनमानी छेड़छाड़ का विरोध करते हैं उनको विकास विरोधी ठहरा कर चुप करवाने के प्रयास होते रहते हैं। मामला एक जोशीमठ का नहीं है, हिमालय में जहां भी अंधाधुंध विकास का मॉडल लागू किया गया है वहां कमोबेश इसी तरह की समस्याएं सामने आई हैं।

किन्तु उनको लीपापोती वाली भाषा से टालने का काम ही किया गया है। समाधान तलाशने की ओर देखा नहीं गया है। हिमालय वासी स्वयं भी इस मामले में ज्यादा जागरूक नहीं रहे हैं। विकास के अंध पैरोकारों के दबदबे ने विरोध के स्वरों को दबा दिया। पर्यावरणीय दृष्टि से कुछ सावधानियां प्रयोग करने के लिए भी जो छोटे-मोटे प्रावधान हुए हैं उनको भी लागू करने की व्यवस्थाएं इतनी लचर और प्रोजेक्ट लागू करने वालों को अंधी छूट देने वाली साबित हुई हैं जिससे उन प्रावधनों का महत्व ही समाप्त हो जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जनसुनवाई कभी भी लोगों को जागरूक करके नहीं होती है बल्कि कोशिश की जाती है कि लोगों को कम से कम पता लगे ताकि योजना निर्माता अपने समर्थकों को इकट्ठा करके योजना के हक की बातों को आगे लाकर अपना रास्ता साफ कर सकें। प्रभाव आकलन का काम परियोजना निर्माताओं द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाता है। जाहिर तौर पर निर्माता परियोजना से खतरों को कम करके दिखाता है। परियोजना प्रभाव आकलन रिपोर्ट स्वतंत्र एजेंसी से बनवानी चाहिए। मौके पर निर्माण कार्य कैसे चल रहा है, कोई नहीं देखता। यहां तक कि निर्माण कार्यों में निकलने वाले मलबे की डम्पिंग करने के प्रावधानों का खुला उल्लंघन होता है किन्तु कोई नहीं सुनता। हिमालय में बन रही सडक़ों या विद्युत परियोजनाओं में ऐसी घटनाएं हर कहीं सामान्य बात बन गई हैं। निर्माण स्थलों पर वनों की स्वीकृति से कई गुणा ज्यादा तबाही की जाती है किन्तु कोई नहीं देखता। कुछ प्रोजेक्टों पर जुर्माने भी लगे हैं किन्तु फिर भी मनमानी कहां रुकती है। गढ़वाल के चंबा से भी कुछ मकान धंसने की खबरें आ रही हैं।

उत्तराखंड में और भी कई इलाके खासकर बिजली प्रोजेक्टों और बड़ी खुली फोरलेन सडक़ों के कारण खतरे में आ रहे हैं। हिमाचल भी इस तरह की त्रासदी से बचा नहीं है। प्रदेश में 450 के करीब जल विद्युत परियोजनाएं बन चुकी हैं, जिनसे 12000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकार की 27000 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है। इन परियोजनाओं से जगह-जगह बस्तियों को खतरा पैदा हुआ है। नाथपा झाकड़ी परियोजना की सुरंग के ऊपर बसे नाथपा, कंडार और निगुल्सेरी गांव धंसने लगे हैं। किन्नौर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर कड़छम वांगतू प्रोजेक्ट सुरंगें गुजरने के कारण उर्नी ढांक में एक स्थाई भूस्खलन बन गया है। जंगी-ठोपन परियोजना का कार्य अभी चल रहा है जिससे जंगी, रारंग, अक्पा और खदरा गांव को खतरा पैदा हो गया है। भरमौर में बन रही होली-बजोली परियोजना की टनल में दरार आने से इन्दौता गांव को भारी नुकसान हुआ है। जमीन धंस रही है, कई मकानों में दरारें आ गई हैं। हिमाचल में चार फोरलेन सडक़ें बन रही हैं। उनके निर्माण में भी नुकसान हो रहा है जिसका कोई जायजा नहीं लिया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि हिमालय में बड़े पैमाने के निर्माण कार्य बहुत सावधानी से किये जाने चाहिए और इसके लिए पर्वतीय विकास का अलग मॉडल विकसित किया जाना चाहिए जिसके लिए हिमालयी क्षेत्रों से लंबे समय से आवाजें उठाई जा रही हैं, किन्तु कोई परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है।

हिमालय में करणीय और अकरणीय गतिविधियों की सूची बननी चाहिए और निर्माण कार्यों एवं उद्योग स्थापना, खनन आदि कार्यों में उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हिमालयी राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार पर दबाव डाल कर पर्वतीय विकास के लिए अलग विकास मॉडल बनवाने का प्रयास करें और केंद्र सरकार एसजेड कासिम की अध्यक्षता वाली कमेटी की रपट का अध्ययन करके और वर्तमान में नीति आयोग द्वारा बनाए गए हिमालयी क्षेत्रीय परिषद को इस काम पर लगाना चाहिए और विश्वव्यापी अनुभवों के आधार पर पर्वतीय विकास का पर्यावरण मित्र मॉडल विकसित करना चाहिए, ताकि विकास की अंधी दौड़ में होने वाले स्थायी नुकसानों से बचा जा सके और टिकाऊ विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

शिक्षा-खेल विभाग में समन्वय स्थापित हो

भूपिंदर सिंह

आज का विद्यार्थी फिटनेस व मनोरंजन के नाम पर दूरसंचार माध्यमों का कमरे में बैठ कर खूब दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात मजाक लगती है। आज के विद्यार्थी के लिए विद्यालय या घर पर आधे घंटे के फिटनेस कार्यक्रम की सख्त जरूरत है। इसमें 15 से 20 मिनट धीरे-धीरे दौडऩा तथा विभिन्न कोणों पर शरीर के जोड़ों की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के बाद शरीर को कूलडाऊन करना होगा। कम से कम बीस मिनटों तक तेज चलने, दौडऩे व शारीरिक क्रियाओं को करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है'

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कदम-कदम पर विद्यालय खुलने तथा विद्यालय से घर तक आना-जाना जब अब वाहन से हो रहा है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का ग्रामीण परिवेश भी अब शहरों व कस्बों में बदल रहा है, ऐसे में विद्यार्थियों के आराम की सुख-सुविधाओं में तो बढ़ौतरी हो रही है, मगर उन का फिटनेस स्तर दिन-प्रतिदिन नीचे गिर रहा है। इसलिए विद्यालय स्तर से फिटनेस कार्यक्रम की बहुत ज्यादा जरूरत है व इसके लिए शिक्षा और खेल विभाग में समन्वय स्थापित करना जरूरी हो जाता है ताकि हम विद्यालय स्तर पर फिटनेस कार्यक्रम लागू कर सकें। किसी भी देश को इतनी क्षति युद्ध या महामारी से नहीं होती है जितनी तबाही नशे के कारण हो सकती है। आज जब देश के अन्य राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में भी नशा युवा वर्ग पर ही नहीं किशोरों तक चरस, अफीम, स्मैक, नशीली दवाओं तथा दूरसंचार के माध्यमों के दुरुपयोग से शिकंजा कस रहा है, इसलिए सरकार, विद्यालय प्रबंधन व अभिभावकों को इस विषय पर सचेत हो जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी किशोरावस्था में नशे से बच जाता है तो वह फिर युवावस्था आते आते समझदार हो गया होता है। माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विद्याओं में व्यस्त रखने के साथ साथ शारीरिक फिटनेस की तरफ मोडऩा बेहद जरूरी हो जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा के बिना अधूरा है।

शिक्षा की परिभाषा में साफ-साफ लिखा है कि यहां शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से बराबर विद्यार्थियों का विकास करना है जिससे वे आगे चलकर जीवन को सफलतापूर्वक खुशहाल जी सकें। शारीरिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से फिटनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। खेल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी को नशे से दूर रखा जा सकता है। पड़ोसी राज्य पंजाब एक समय तरक्की में देश का अग्रणी राज्य था। इस सबके पीछे कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों की दूरगामी सोच थी। खेलों में उत्कृष्टता उस प्रदेश की तरक्की व खुशहाली का भी पैमाना होती है। पंजाब में हजारों प्रशिक्षक विभिन्न खेलों में खेल प्रशिक्षण के लिए नियुक्त होने के साथ-साथ खेल प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा होना वहां के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख कारण रहा था। बाद में जब पंजाब धीरे-धीरे खेलों से दूर हुआ तो पहले वहां आतंकवाद और फिर आजकल पंजाब नशे का अड्डा बना हुआ है। यही कारण है कि हर क्षेत्र में आज हरियाणा पंजाब से काफी आगे निकल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एशियाई, राष्ट्रमंडल व ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होने पर खिलाडियों को करोड़ों रुपए के नगद ईनाम व सम्मानजनक नौकरी देकर हरियाणा में खेलों के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा का हर किशोर व युवा किसी न किसी खेल के मैदान में नजर आता है। हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की खेलों के लिए अपने पहले कार्यकाल से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड, सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण तथा देश में प्रशिक्षक कैडर डाईंग हो जाने के बाद पहली बार चालीस प्रशिक्षकों की भर्ती जैसे बहुत बड़े खेल सुधार किए।

हिमाचल प्रदेश की खेल सुविधाओं का प्रयोग राज्य में स्वास्थ्य व खेलों के लिए बड़े स्तर पर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश इस समय शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। फिछले कुछ दशकों से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की फिटनेस में बहुत कमी आई है। इसका प्रमुख कारण विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम का न होना है। रट्टे वाली पढ़ाई की होड़ में हम विद्यार्थियों की फिटनेस को ही भूल गये हैं। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। वहां पर सवेरे-शाम वर्षों पहले विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ कृषि व अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करता था। विद्यालय आने-जाने के लिए कई किलोमीटर दिन में पैदल चलता था। इसलिए उस समय के विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं थी। आज का विद्यार्थी घर के आंगन में बस पर सवार होकर विद्यालय के प्रांगण में उतरता है। पढ़ाई के नाम पर ज्यादा समय खर्च करने के कारण फिटनेस के लिए कोई समय नहीं बचता है। अधिकांश स्कूलों के पास फिटनेस के लिए न तो आधारभूत ढांचा है और न ही कोई कार्यक्रम है। आज का विद्यार्थी फिटनेस व मनोरंजन के नाम पर दूरसंचार माध्यमों का कमरे में बैठ कर खूब दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात मजाक लगती है।

ब्रीफ न्यूज

किसानों के लिए जरूरी खबर, खाते में चाहिए 2 हजार रुपये तो 28 जनवरी तक कर लें यह काम

जल्द ही पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त किसानों के खातों में आने वाली है। पीएम किसान की किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। बिहार सरकार ने किसानों से 28 जनवरी तक ई-केवाईसी करवाने को कहा है। बिना केवाईसी के पीएम किसान का फायदा नहीं मिलेगा।

नई दिल्ली : पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की 13वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी (PM Modi) जल्द ही करोड़ों किसानों के खातों में यह किस्त जारी कर सकते हैं। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत लाभार्थी किसानों को साल में 6,000 रुपये मिलते हैं। यह रकम 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में मिलती है। पीएम किसान की 12वीं किस्त करीब 2 करोड़ लोगों को नहीं मिल पायी थी। लाभार्थी किसानों का रिकॉर्ड सेंट्रल डेटाबेस में अपडेट नहीं होने के चलते इन किसानों को पिछली किस्त नहीं मिल पायी थी। इस बार राज्य सरकारें 13 वीं किस्त (PM Kisan 13th Installment) से पहले किसानों का रेकॉर्ड सेंट्रल डेटाबेस में दर्ज करने में लगी हैं। वहीं, 13 वीं किस्त का फायदा पाने के लिए किसानों को समय पर ई-केवाईसी (PM Kisan e-KYC) भी करानी होगी।

जरूर करवा लें ई-केवाईसी

पीएम किसान की वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए ईकेवाईसी (eKYC) जरूरी है। अगर आपकी ईकेवाईसी नहीं हुई है, तो आपको पीएम किसान की किस्त का फायदा नहीं मिल पाएगा। ओटीपी बेस्ड ईकेवाईसी की सुविधा पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा बायोमैट्रिक बेस्ड ईकेवाईसी के लिए पास के सीएससी सेंटर्स में संपर्क किया जा सकता है।

राज्य सरकारें कर रहीं अनुरोध

राज्य सरकारें लाभार्थी किसानों से अनुरोध कर रही हैं कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी कर लें। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि लाभार्थी 28 जनवरी तक पीएम किसान के लिए ई-केवाईसी पूरी कर लें। विभाग ने कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन 13वीं किस्त से पहले अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

इस तरह करें ई-केवाईसी

स्टेप 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा।

स्टेप 2. अब किसान कॉर्नर विकल्प पर eKYC लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4. इसके बाद यहां मांगी गई जरूरी जानकारियों को दर्ज करें।

स्टेप 5. इसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

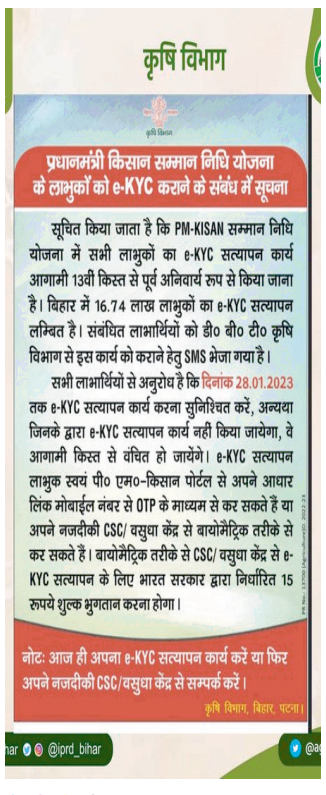

पहली बार प्रॉफिट में आई टाटा ग्रुप की यह कंपनी, आठ साल पहले हुई थी शुरुआत

एनटीवी न्यूज

टाटा ग्रुप (Tata Group) की एयरलाइन कंपनी विस्तारा (Vistara) करीब आठ साल में पहली बार मुनाफे में आई है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। इस कंपनी ने 2015 की शुरुआत में भारत में अपना ऑपरेशन शुरू किया था। इसमें टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी है।

नई दिल्ली: टाटा ग्रुप (Tata Group) देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में है। इस ग्रुप की कई कंपनियां जोरदार मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन ग्रुप की एक कंपनी पहली बार मुनाफे में आई है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी विस्तारा (Vistara) ने दिसंबर तिमाही में पहली बार मुनाफा कमाया है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि उसने मुनाफे की रकम का खुलासा नहीं किया। विस्तारा ने साथ ही कहा कि उसका रेवेन्यू एक अरब डॉलर को पार कर गया है और इस फिस्कल ईयर में उसका एबिटा (EBITDA) पॉजिटिव रहा है। विस्तारा में टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस का निवेश है। इसकी शुरुआत नौ जनवरी, 2015 को हुई थी और अभी इसके बेड़े में 52 एयरक्राफ्ट हैं।

विस्तारा के सीईओ विनोद कन्नन ने कहा कि यह साल 2022 कंपनी के लिए शानदार रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान कंपनी ने अपने नेटवर्क और फ्लीट में इजाफा किया है। विस्तारा में 5,000 से अधिक कर्मचारी हैं और यह हर महीने करीब 8,500 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। दिसंबर 2022 में घरेलू बाजार में इसकी हिस्सेदारी 9.2 फीसदी थी। पिछले साल नवंबर में सिंगापुर एयरलाइंस ने विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज करने की घोषणा की थी। एयर इंडिया की हाल में टाटा ग्रुप में वापसी हुई थी।

एक छत के नीचे आएगा एयरलाइन बिजनस

टाटा ग्रुप अपने सारे एयरलाइन बिजनस को एक ब्रैंड के नीचे लाने की तैयारी कर रहा है। इससे एयर एशिया इंडिया (AirAsia India) और विस्तारा दोनों एयर इंडिया में मिल जाएंगी। टाटा ग्रुप ने इन तीनों एयरलाइन को एक साथ लाने की कवायद भी शुरू कर दी है। टाटा समूह ने पिछले साल अक्टूबर में 18,000 करोड़ रुपये में एयर इंडिया को खरीदा था। मलेशिया की एयरलाइन एयरएशिया (AirAsia) ने एयरएशिया इंडिया (AirAsia India) में अपनी शेष 16.33 फीसदी हिस्सेदारी एयर इंडिया (Air India) को बेच दी है। एयरएशिया इंडिया ने जून, 2014 में भारत में उड़ानें शुरू की थीं। एयरएशिया ग्रुप की भारत में आठ साल की यात्रा काफी मुश्किलों भरी रही। उसका घाटा लगातार बढ़ रहा था।

अब आठ कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस उतारने की तैयारी, जानिए किन दो राज्यों को मिल सकती है अगली ट्रेन

देश में अभी 16 कोच की आठ वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आठ कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस उतारने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड ने आईसीएफ को आठ कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने को कहा है। इन ट्रेनों को ऐसे रूट्स पर चलाया जा सकता है जहां पैसेंजर्स कम हैं।

नई दिल्ली: देश में अभी आठ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें (Vande Bharat Express Train) चल रही हैं। नौवीं ट्रेन अगले महीने पटरी पर आ सकती है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक इसे पश्चिम बंगाल के हावड़ा और ओडिशा के पुरी के बीच चलाया जा सकता है। इस तरह यह पश्चिम बंगाल की दूसरी और ओडिशा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। पिछले महीने हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। हाल ही में तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम के बीच देश की आठवीं वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। इस बीच रेलवे ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) को पायलट के तौर पर आठ कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने को कहा है। अभी इस फैक्ट्री में 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें बनाई जा रही हैं।

सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अब तक केवल आठ वंदे भारत ट्रेनें ही चलाई जा सकी हैं। विभिन्न राज्यों की ओर से इन ट्रेनों को चलाने की मांग बढ़ रही है। इसलिए 16 के बजाय आठ कोच वाली वंदे भारत ट्रेन बनाने पर विचार चल रहा है। इससे बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही आठ कोच वाली ट्रेनों को ऐसे रूट्स पर चलाया जा सकता है जहां मांग कम है। सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे रूट्स हैं जहां ज्यादा पैसेंजर्स नहीं हैं। ऐसे रूट्स पर आठ से 12 कोच वाली ट्रेनों को चलाया जा सकता है।

रेलवे को होगी आसानी

रेलवे बोर्ड ने आईसीएफ को भेजे एक पत्र में कहा कि कॉन्सेप्ट के तौर पर आठ डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का फैसला किया गया है। इसे 12, 16, 20 और 24 डिब्बों तक बढ़ाया जा सकता है। किस रूट पर कितने डिब्बे होंगे, इसका फैसला ट्रैफिक के हिसाब से तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आठ डिब्बों वाली ट्रेन के डिजाइन को फाइनल किया जाएगा और पायलट के तौर पर एक रैक बनाया जाएगा। कोच की संख्या कम होने से अधिक से अधिक सीटें बनाने का प्रयास किया जाएगा लेकिन यात्री सुविधाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

अभी देश में आठ वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन में डिब्बों की संख्या कम होने से रिपेयर और मेंटनेंस में आसानी होगी। इसकी वजह यह है कि सामान्य ट्रेनों से अलग वंदे भारत ईएमयू की तरह है। रिपेयर और मेंटनेंस के लिए पूरी ट्रेन को यार्ड में ले जाना पड़ता है। किसी भी वंदे भारत ट्रेन के पास स्पेयर कोच या रैक्स नहीं है। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने आईसीएफ को फ्रंट नोज कोन्स बनाने को कहा है ताकि मामूली दुर्घटना की स्थिति में इसे तेजी के साथ बदला जा सके। हाल में वंदे भारत ट्रेन से मवेशियों के टकराने की कई घटनाएं हुई हैं। इनमें ट्रेन के अगले भाग को क्षति पहुंची है।

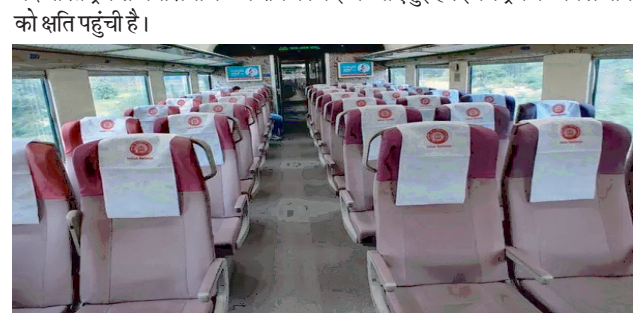

शिमला, मसूरी, नैनीताल में कम हुई पर्यटकों की दिलचस्पी! जानिए क्या है उनका नया ठिकाना

कोरोना का प्रकोप कम होते ही देश में पर्यटन गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी हैं। लेकिन अब पर्यटक जाने माने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बजाय कम चर्चित जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं। इनमें तेलंगाना का माधापुर, तमिलनाडु में रामेश्वरम और वैल्लूर, मेघालय का चेरापूंजी और महाराष्ट्र का पिंपरी-चिंचवाड़ शामिल है।

नई दिल्ली: देश के पर्यटकों में कम चर्चित टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। पिछले साल तेलंगाना का माधापुर, तमिलनाडु के रामेश्वरम और वैल्लूर, मेघालय का चेरापूंजी और महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवाड़ शीर्ष पसंदीदा पर्यटक स्थल बनकर उभरे हैं। वैकेशन रेंटल कंपनी एयरबीएनबी (Airbnb) के सोमवार को जारी आंकड़ों से यह रुझान सामने आया है। इससे पता चलता है कि वर्ष 2022 में अंतरराष्ट्रीय यात्रा में भी मजबूत रिवाइवल हुआ है। यह चलन 2023 में भी जारी रहने की संभावना है। एयरबीएनबी के मुताबिक, भारतीयों ने दुनियाभर के सबसे लोकप्रिय शहरों को खोजा। इसके अलावा सिंगल विजिट 2022 की जुलाई-सितंबर तिमाही में सबसे लोकप्रिय रूझान के रूप में सामने आई। एयरबीएनबी ने कहा कि कम-चर्चित जगहों की यात्राएं करने के रूझान से स्थानीय कम्युनिटीज को लाभ मिला और टूरिज्म रिवाइवल में भी मदद मिली।

इसमें कहा गया कि घरेलू स्तर पर भारतीयों ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मेघालय और तेलंगाना जैसे राज्यों में घूमने का मन बनाया। वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में भारतीय पर्यटकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जानकारी दुबई, लंदन, पेरिस, टोरंटो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के बारे में जुटाई। हॉस्पिटैलिटी के मामले में एयरबीएनबी पर लोगों ने सबसे ज्यादा अंक दिल्ली, गोवा, केरल, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश को दिए। वहीं, 2022 में घरेलू स्थानों पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले स्थलों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता थे।

इस साल कहां जाएंगे टूरिस्ट

एयरबीएनबी के जनरल मैनेजर (भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, हांगकांग और ताइवान) अमनप्रीत बजाज ने कहा, 'ऐसा अनुमान है कि यात्री इस वर्ष बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर जाएंगे और भारत में उन स्थलों की यात्रा करेंगे जो मशहूर पर्यटन स्थलों में नहीं गिने जाते। यात्रा की बढ़ती इच्छा एक सकारात्मक संकेत है।' आंकड़ों के मुताबिक, भारत में 2022 में सर्वाधिक संख्या में बुकिंग मुंबई, नई दिल्ली, गुवाहाटी, गोवा और हैदराबाद के लिए हुई।

शादियों के सीजन में सस्ते सोने के लिए हो जाएं तैयार, आयात शुल्क घटाने की तैयारी कर रही सरकार

नई दिल्ली : कीमती धातु सोने से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं। भारत जल्द ही सोने पर आयात शुल्क (Import Duty on Gold) घटा सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि सोने की स्मगलिंग को रोकने के लिए सरकार यह कदम उठा सकती है। कोविड-19 के बाद से सोने के अवैध आयात में काफी तेजी आई है। सरकार इससे निपटने के लिए सोने के आयात शुल्क को कम कर सकती है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता देश में आयात शुल्क घटने से सोने की कीमतों (Gold Prices) में गिरावट आएगी। शादियों के सीजन से पहले सोना सस्ता होने से खुदरा बिक्री बढ़ सकती है। इससे घरेलू गोल्ड रिफाइनरीज को भी राहत मिलेगी। पिछले दो महीनों से ये रिफाइनरीज ग्रे-मार्केट ऑपरेटर्स के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही हैं।

सोने की कीमतों में दिखा उछाल

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने के घरेलू वायदा भाव में तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर 3 फरवरी, 2023 की डिलीवरी वाला सोना 116 रुपये की तेजी के साथ 56,774 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 5 अप्रैल 2023 की डिलीवरी वाला सोना 57,016 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सपाट ट्रेड करती दिखी चांदी

चांदी की बात करें तो यह सोमवार शाम सपाट ट्रेड करती दिखी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर 3 मार्च 2023 की डिलीवरी वाली चांदी 0.04 फीसदी या 25 रुपये की मामूली तेजी के साथ 68,572 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

सोने का वैश्विक भाव

वैश्विक स्तर की बात करें, तो सोमवार शाम सोने का वायदा और हाजिर भाव भारी गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे। ब्लूमबर्ग के अनुसार, सोने का वैश्विक वायदा भाव (Global Gold Price) कॉमेक्स पर सोमवार शाम 0.10 फीसद या 2 डॉलर की गिरावट के साथ 1942.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सोने का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 0.04 फीसद या 0.70 डॉलर की गिरावट के साथ 1925.38 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी के वैश्विक भाव (Global Silver Price) की बात करें तो सोमवार शाम इसकी वायदा और हाजिर दोनों कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ब्लूमबर्ग के अनुसार, सोमवार शाम चांदी का वैश्विक वायदा भाव कॉमेक्स पर 0.58 फीसद या 0.14 डॉलर की गिरावट के साथ 23.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 0.91 फीसद या 0.22 डॉलर की गिरावट के साथ 23.71 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

प्रचंड जीत के बाद सबसे बड़े बजट की तैयारी में भूपेन्द्र सरकार, क्या लोगों को मिलेगा 'रिटर्न गिफ्ट'

गुजरात विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल आचार्य देवव्रत अभिभाषण देंगे। अगले दिन 24 फरवरी राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई अपना दूसरा और नई सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। नई सरकार के पहले बजट से लोगों को राहत की काफी उम्मीदे हैं।

अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत देशभर में छाई हुई है। 27 साल की सत्ता के बाद भी रिकॉर्डतोड़ जीत के बाद अब रिटर्न गिफ्ट की बारी है। इसके लिए भूपेन्द्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। भूपेन्द्र पटेल (Bhupendra Patel) का बजट न सिर्फ ऐतिहासिक होगा। यह न सिर्फ अब तक सबसे बड़ा बजट होगा, बल्कि इसमें कई बड़े ऐलान किए जाने की संभावना है। 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले दिन राज्यपाल आचार्य देवव्रत का अभिभाषण होगा। तो दूसरे वित्त मंत्री कनु देसाई 2023-2024 के बजट पेश करेंगे।

देसाई का दूसरा बजट

वित्त मंत्री कनु देसाई विधानसभा में दूसरी बार गुजरात का बजट पेश करेंगे। भूपेन्द्र पटेल (Bhupendra Patel) के पिछले कार्यकाल में उन्होंने 2022-2023 का बजट पेश किया था। यह गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। 2,43,965 करोड़ रुपये का उन्होंने बजट पेश किया था। इसमें देसाई ने गुजरात की जनता पर कोई नय कर नहीं लगाया था। नई सरकार के कार्यकाल के पहले बजट में लोगों की अपेक्षा पूरी होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने जब पिछला बजट पेश किया था तो उसके बाद सरकार को चुनावों में जाना था। अब जब वे दूसरी बजट पेश करेंगे तो आगे लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में वित्त मंत्री के द्वारा इस बजट में कोई नया कर लगाने या फिर जनता पर नया बोझ डालने की संभावना नहीं है।

राहत की नहीं गुंजाइश

गुजरात के वरिष्ठ अर्थ विशेषज्ञ हेमंत शाह कहते हैं कि सरकार के हाथ बंधे हुए है। उनके पास गुजाइंश नहीं है कि लोगों को राहत दे पाएं, क्योंकि राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। 2001 में गुजरात पर 20 हजार करोड़ का कर्ज था जो बढ़कर साढ़े तीन लाख करोड़ हो चुका है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि सरकार लोगों को प्रचंड जीत के बदले रिटर्न गिफ्ट जैसा कुछ देगी। राज्य में पहले से ही लोगों के ऊपर काफी टैक्स है। ऐसे में सरकार से कोई बड़ी राहत की उम्मीद मुझे इस बजट में दिखाई नहीं दे रही है।

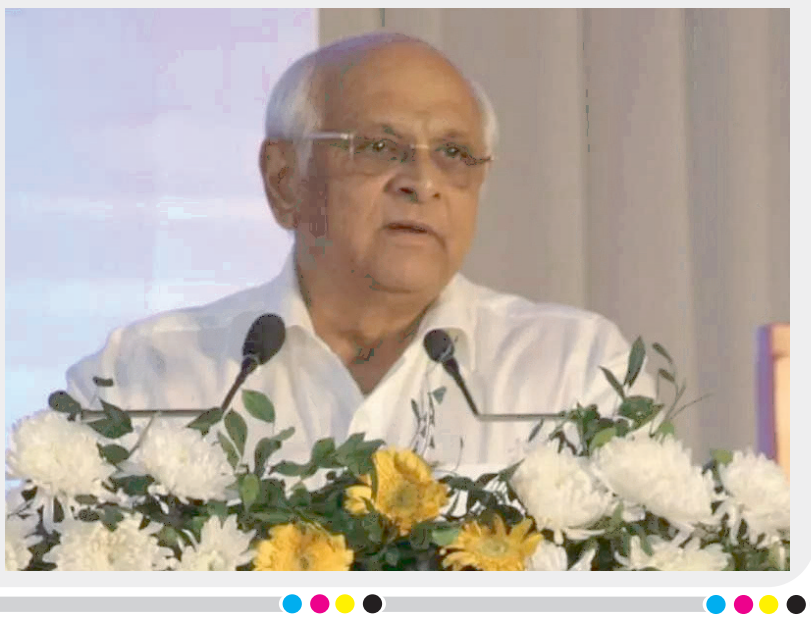

कोरोना के बाद अब भारत में नोरोवायरस दे रहा टेंशन, आखिर कैसे फैलती है यह बीमारी, जानें लक्षण से लेकर इलाज तक सबकुछ

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी हो रही है। इस बीच केरल में एक नए वायरस के संक्रमण ने टेंशन बढ़ा दी है। राज्य में नोरोवायरस के पांच मामलों की पुष्टि हुई है। तीन बच्चों का अभी इलाज चल रहा है। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक स्कूल में 63 बच्चे को अचानक उल्टी और डायरिया की शिकायत हुई। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्राइवेट स्कूल को अगले दो-तीन दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। खास बात है कि बच्चों के अलावा कुछ पैरेंट्स में भी इस बीमारी के लक्षण देखने को मिले हैं। जानते हैं आखिर यह नोरोवायरस है क्या। इस संक्रमण के लक्षण क्या है। क्या इसका इलाज संभव है।

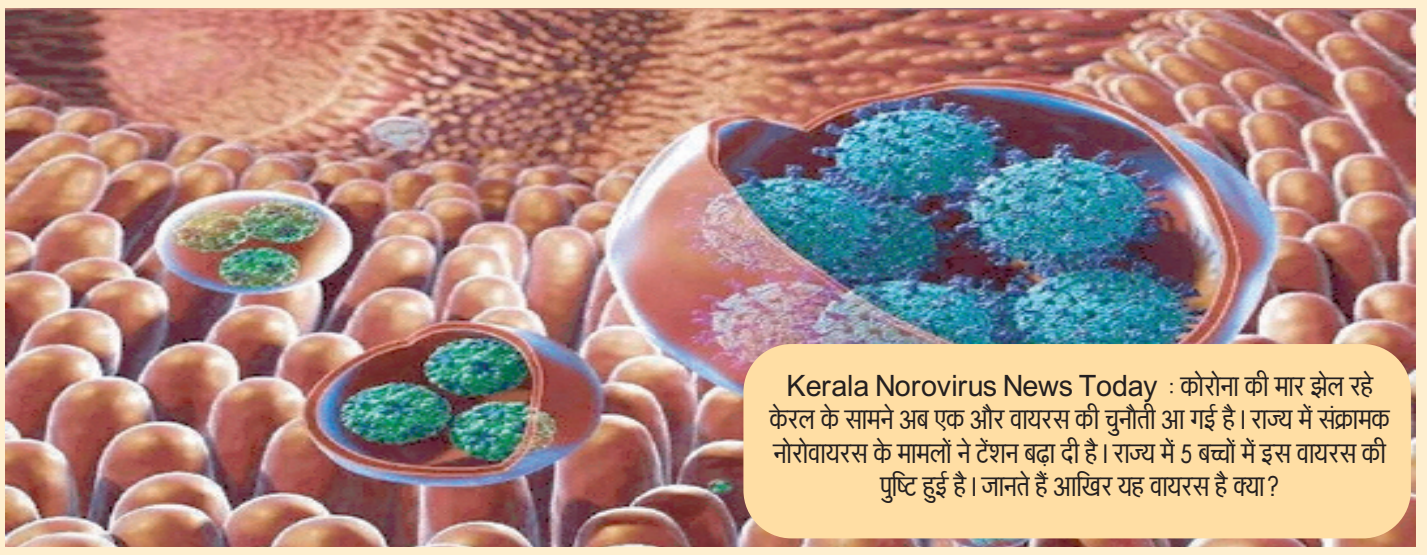

Kerala Norovirus News Today : कोरोना की मार झेल रहे केरल के सामने अब एक और वायरस की चुनौती आ गई है। राज्य में संक्रामक नोरोवायरस के मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। राज्य में 5 बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। जानते हैं आखिर यह वायरस है क्या?

नोरोवायरस क्या है, कैसे फैलता है ?

नोरोवायरस एक बेहद ही संक्रामक वायरस है। नोरोवायरस को विंटर वोमिटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। नोवोवायरस संक्रमण में व्यक्ति को तेज उल्टी और डायरिया होता है। कई लोग नोरोवायरस को 'द स्टमक फ्लू' भी कहते हैं। हालांकि, इसका फ्लू या इंफ्लूएंजा से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर तेजी से फैलता है। इसके अलावा यह दूषित भोजन से भी फैलता है। इस संक्रामक वायरस का असर दो दिन से लेकर 6 दिन तक रहता है।

नोरोवायरस संक्रमण फैलने का कारण

दूषित पानी पीने से।
दूषित भोजन खाने से।
दूषित जगह या वस्तु के संपर्क में आने के बाद मुंह पर हाथ लगाने से नोरोवायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से

किसे है सबसे अधिक खतरा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल नोरोवायरस के दुनियाभर में 68 करोड़ मामले सामने आते हैं। खास बात है कि इसमें से 20 करोड़ संक्रमित 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। इस बीमारी से दुनियाभर में हर साल करीब दो लाख लोगों की मौत होती है। मरने वालों में बच्चों की संख्या लगभग 50 हजार होती है। एक्सपर्ट का कहना है कि नोरोवायरस से सबसे अधिक खतरा कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को होता है। ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों में इसके संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। कम आय वाले देशों में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है।

क्या हैं इस बीमारी के लक्षण

उल्टी
डायरिया
जी मिचलाना
पेट में दर्द या मरोड़ उठना
हल्का बुखार
सिरदर्द और बदन दर्द

नोरोवायरस का इलाज

नोरोवायरस को लेकर कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है। इस संक्रमण में डॉक्टर रोगी को अधिक से अधिक लिक्विड लेने की सलाह देते हैं। इस बीमारी में शरीर में पानी की कमी होने से रोकने पर जोर होता है। इसके अलावा आराम करने की सलाह दी जाती है। साथ ही ऐसा भोजन खाने की सलाह दी जाती है जो आसानी से पच सके।

'लंबे-चौड़े वादे किए फिर लद्दाख के लोगों को धोखा दिया', कांग्रेस अध्यक्ष खरगे क्यों कर रहे हैं मोदी सरकार की आलोचना

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने और पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा की मांग को न मानकर लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय लोगों की सुरक्षा की मांग को न मानकर सरकार रणनीतिक सीमा क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है।

लंबे-चौड़े वादे के बावजूद विश्वासघात

खरगे ने ट्विटर पर कहा, 'नरेंद्र मोदी जी, लद्दाख के लोग एकजुट होकर केंद्रशासित प्रदेश के लिए राज्य की मांग कर रहे हैं और संविधान की छठी अनुसूची के तहत क्षेत्र के जनजातीय लोगों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार ने लंबे-चौड़े वादे करने के बावजूद उनके साथ विश्वासघात किया है।' यूट्यूब पर साझा किए गए एक वीडियो में लद्दाख के समाज सुधारक सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कहा कि अध्ययनों में केंद्रशासित प्रदेश में दो तिहाई ग्लेशियरों के विलुप्त होने की बात कही गई है।

वांगचुक ने ट्विटर पर पोस्ट किया था वीडियो

बॉलीवुड फिल्म '3 इडियट्स' वांगचुक के जीवन से प्रेरित है। प्रधानमंत्री से संविधान की छठी अनुसूची के तहत नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप की अपील करते हुए वांगचुक ने अपने वीडियो में कहा, ₹यह लद्दाख (भारतीय हिमालय में) में सोनम वांगचुक की भारत और दुनिया के लोगों से लद्दाख के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा में मदद करने की तत्काल अपील है।

खरगे ने कहा- लद्दाख की आवाज सुनें

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आरोप लगाया कि लद्दाख के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हिमालयी ग्लेशियरों का दोहन करने का, इच्छुक मोदी सरकार के ₹चुनिंदा मित्रों को लाभ पहुंचाने का लालच₹ जगजाहिर है। उन्होंने ट्वीट किया, ₹संवैधानिक सुरक्षा से इनकार करके, आप रणनीतिक सीमा क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। लद्दाख की आवाज सुनें।

इनसाइड

बांदा में साढ़े 7 अरब के निवेश का प्रस्ताव, 2 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार की उम्मीद

बांदा जिले में मंगलवार को इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 77 इन्वेस्टर्स की ओर से तकरीबन 7 अरब के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है।

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिला मुख्यालय में स्थित रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सभागार में मंगलवार को इन्वेस्टर्स सम्मिट होगी। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए जिले के 77 उद्यमियों की ओर से अब तक 7 अरब 50 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही इसमें दावा किया गया है कि उद्योग लगने पर यहां के 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कारोबार करने वाले उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन ऋण में छूट दिलाई जाएगी।

2 फैक्ट्रियां बंद

बुंदेलखंड के अधिकांश जिलों में रोजगार के अभाव में लोग गैर प्रांतों में पलायन कर जाते हैं और वहां निजी फैक्ट्रियों में काम करके परिवार का गुजर-बसर करते हैं। 90 के दशक में यहां पर कताई मिल लगाई गई थी। जो कुछ ही सालों बाद बंद हो गई। इसी तरह अविभाजित जनपद के चित्रकूट स्थित बरगढ़ में ग्लास फैक्ट्री भी लगाई गई थी, जिसमें कई हजार लोगों के रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की गई थी लेकिन यह फैक्ट्री भी शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि स्थानीय उद्यमी यहां उद्योग लगाएं ताकि बाहर रोजगार की तलाश में लोगों को बाहर न जाना पड़े।

2000 लोगों को रोजगार की आशा

मंगलवार को होने वाले इन्वेस्टर्स समिट में निजी कंपनियों की ओर से निवेश के लिए जो प्रस्ताव दिए गए हैं। उसके मुताबिक लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जो प्रस्ताव दिए गए हैं उसमें होटल, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, फ्लोर मिल, राइस मिल, डेयरी प्लांट, बायोफ्यूल हॉर्टिकल्चर, नमकीन उद्योग, पाइप, ऑयल मिल, फूड प्रोडक्ट, कृषि यंत्र ट्रेडर्स और मनोरंजन से संबंधित रिसॉर्ट आदि शामिल हैं।

कारोबारियों को दी जाएगी छूट

बताते चलें कि प्रदेश सरकार निजी कारोबारियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत उद्योग लगाने वालों को जीएसटी में छूट से राहत मिल सकेगी। बिजली कनेक्शन और बिल में भी छूट मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। जमीन न होने पर निजी क्षेत्र में जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। ऋण लेने पर अनुदान अथवा ब्याज में छूट दी जाएगी। अभी तक फिलहाल जिले के 77 कारोबारियों ने 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है।

वाराणसी में जल्द लगेगी प्राकृतिक पेंट बनाने वाली प्रदेश पहली यूनिट, प्रॉडक्शन के साथ ही ट्रेनिंग भी मिलेगी

खादी के नैचुरल पेंट को केंद्र सरकार में मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से 12 जनवरी, 2021 को लांच किया गया था। और इसके पीछे का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना। और साथ ही देशभर में स्वरोजगार पैदा करना था।

वाराणसीः खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जल्द ही वाराणसी के सेवापुरी में प्राकृतिक पेंट की विनिर्माण इकाई चालू करेगा। प्राकृतिक पेंट का पहला संयंत्र जयपुर के कुमारप्पा नेशनल हैंडमेट पेपर इंस्टीट्यूट (केएनएचपी) में 2021 में स्थापित किया गया था। माघ मेले में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विनीत कुमार ने बताया कि वाराणसी के सेवापुरी में दो-तीन महीने में प्राकृतिक पेंट बनाने की इकाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस इकाई में उत्पादन के साथ ही लोगों को प्राकृतिक पेंट तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि भविष्य में वे अपना उद्यम लगा सकें। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के मंडलीय कार्यालय, वाराणसी के निदेशक रितेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सेवापुरी में लगने वाला यह प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक पेंट का पहला प्रशिक्षण केंद्र होगा।

बिना पैराशूट के क्यों हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता है 'यात्री विमान', जानिए इसके पीछे की वजह

एनटीवी संवाददाता

आसमान में बादलों को छूते हवाई जहाज तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद हवाई जहाज में एक भी पैराशूट नहीं होता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह...

अगर आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि प्लेन में लाइफ जैकेट होती है,ऑक्सीजन मास्क भी होता है लेकिन पैराशूट नहीं होता है। ऐसे में आपके जहन में भी ये सवाल तो आया ही होगा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद भी प्लेन में पैराशूट क्यों नहीं होता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह....

बिगड़ सकता है प्लेन का संतुलन

कॉमर्शियल विमान कहें या यात्री विमान में पैराशूट नहीं होने की बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि पैराशूट का वजन काफी अधिक होता है। ऐसे में अगर सभी यात्रियों और पायलट के लिए पैराशूट रखा जाए तो प्लेन का वजह काफी हद तक बढ़ जाएगा। जिसके कारण प्लेन का सभी को लेकर हवा में उड़ना काफी खतरनाक साबित हो सकता है।

पैराशूट होता है काफी महंगा

यात्री विमान में पैराशूट नहीं होने की एक वजह उसकी कीमत भी होती है। बता दें कि एक पैराशूट की कीमत 1 लाख अधिक होती है। ऐसे में प्लेन में हर किसी के लिए एक एक पैराशूट रखना विमान कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है।

पायलट के पास भी नहीं होता पैराशूट

कॉमर्शियल विमान में यात्री ही नहीं पायलट के पास भी पैराशूट नहीं होता है। इसकी वजह ये है कि अगर पायलट के पास पैराशूट होगा तो वो यात्रियों को बचाने के बजाय पहले अपनी जान बचाएगा। इसलिए प्लेन कंपनियां यात्री ही नहीं पायलट को भी पैराशूट नहीं देती हैं।

यात्रियों को पैराशूट खोलना नहीं आता

यात्री विमान में पैराशूट नहीं होने की एक अहम वजह यह भी है कि प्लेन में यात्रा कर रहे सभी लोगों को पैराशूट से उतरना नहीं आता है। जिसके कारण अगर वो सही समय पर पैराशूट नहीं खोलेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है।

विमान का डिजाइन

अगर आपने विमान में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि यात्री विमान का डिजाइन प्राइवेट जेट से थोड़ा अलग होता है। इसलिए कॉमर्शियल विमान से यात्री पैराशूट पहनकर प्लेन से नीचे नहीं कूद सकते हैं। ये उनकी जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है।

बस सात दिन और पाकिस्तान का खेल खत्म! जानिए क्यों अमेरिकी पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने कही यह बात

पाकिस्तान (Pakistan) इस समय इतने बड़े संकट (Pakistan Crisis) में है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पिछले साल जब श्रीलंका संकट (Sri Lanka Crisis) में आया जो सबने आशंका जताई कि कहीं भारत का यह पड़ोसी भी तो मुश्किल की तरफ नहीं है। सबने इस बात को खारिज कर दिया। मगर अब खुद पाकिस्तान के ही लोग यह बात मानने लगे हैं।

इस्लामाबादः सन 1947 में भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान आज पूरी तरह से बिखरने की कगार पर आ गया है। भयंकर आर्थिक संकट में घिरे इस देश के पास कुछ ही दिनों का समय बचा है। कुछ लोग अब इस बात की आशंका जताने लगे हैं कि जल्द ही श्रीलंका की ही तरह उनका मुल्क भी कंगाल होने वाला है। पिछले दिनों रिपोर्ट्स आई थीं कि विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 अरब डॉलर का ही बचा है यानी सिर्फ तीन हफ्तों का ही पैसा देश में है। इससे अलग अमेरिका में बसे पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन साजिद तरार की मानें तो बस सात दिन में ही इस देश का गेम ओवर होने वाला है।

होगा श्रीलंका जैसा हाल

साजिद तरार ने ट्वीट किया और लिखा, 'यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अगले सात दिनों में पाकिस्तान और ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। गेम ओवर हो जाएगा। सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह से होने वाली हैं जैसे कि श्रीलंका में हुईं। दोहरे नागरिक अभी तक लूट में बिजी हैं और देश सो रहा है।' पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाले मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले साजिद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े समर्थक हैं। चार बच्चों के पिता साजिद अंतरराष्ट्रीय मामलों की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और फिर यहीं पर बस गए। वह अक्सर पाकिस्तान सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और उनका मानना है कि उन नीतियों की वजह से ही आज देश की यह स्थिति है।

पाकिस्तान में सबकुछ बिखरा

6 जनवरी को आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि देश का मुद्रा भंडार एक दशक बाद सबसे निचले स्तर पर है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपया 20 फीसदी तक गिर गया है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से जल्द ही एक मिनी बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) की तरफ से उठाई गईं चिंताओं का जिक्र होगा। इन चिंताओं की वजह से ही पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज नहीं मिल पा रहा है। आईएमएफ का कहना है कि बेलआउट पैकेज तभी हासिल हो सकेगा जब ये शर्तें पूरी होंगी।

और बढ़ेंगी परेशानियां

पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक ज्यादातर लोग यह मान रहे हैं कि अगर आईएमएफ की शर्तों को लागू किया गया तो आम आदमी की परेशानियां दोगुनी हो जाएंगी। उनकी मानें तो आईएमएफ के प्रस्तावों के बाद देश में महंगाई और बढ़ जाएगी। पहले ही ब्याज दरें आसमान छू रही हैं और महंगाई दर बेकाबू है। यूक्रेन की जंग की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंद रफ्तार के अलावा रोजमर्रा की चीजें भी काफी महंगी हो गई हैं। डॉन के मुताबिक सरकार पहले ही बिजली की कीमतों में 30 फीसदी और गैस की कीमतों में 60 से 70 फीसदी इजाफे का मन बना चुकी है। इसके अलावा नई टैक्स दरों को भी लागू किया जा सकता है। साथ ही ब्याज दरों को और बढ़ाने की तैयारी भी है।